रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. (D.)-73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
15-10-80

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1980/भाद्र 15, 1902

No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980/BHADRA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1980

का० आ० 2185.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 123-कुन्दारा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री उदय भानु, कलकुरुनबुविला, मथीलिल, पेरीनाडु, डाक०, क्वीलोन (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री उदय भानु को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० केरल-वि० स०/123/80(12)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 16th July, 1980

S.O. 2185.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Udaya Bhanu, Kalkurunbuvila, Mathilil, Perinadu, P.O. Quilon (Kerala) a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 123-Kundaia Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Udaya Bhanu to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/123/80(12)]

आदेश

का० आ० 2186.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 123-कुन्दारा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भास्करन पिल्लई, मुलामुट्टिल वीडू, कुझीयाम, पेरीनाडू, चन्द्रनथोप्पू, डाक०, जिला क्वीलोन (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने मे असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भास्करन पिल्लई को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/123/80(13)]

ORDER

S.O. 2186.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhaskaran Pillai, Mulamuttil Veedu, Kuzhiyam, Perinadu, Chandranathoppu P.O., District Quilon (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 123-Kundara Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhaskaran Pillai to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/123/80(13)]

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1980

का० आ० 2187.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 126-चथान्नूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए० अब्दुल समद, पलक्कल अझीकथु वीडू, कुन्दुमन, अदीचानाल्लूर डाक०, क्वीलोन (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ए० अब्दुल समद को ससद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/126/80(14)]

ORDER

New Delhi, the 17th July, 1980

S.O. 2187.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Abdul Samad, Palakkal Azhikathu Veedu, Kunduman, Adichanalloor P.O., Quilon (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 126-Chathannoor Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Abdul Samad to be disqualified for

being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/126/80(14)]

आदेश

का० आ० 2188.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 126-चथान्नूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० के० चन्द्रन, प्लाविला वीडू, कोट्टियम डाक०, क्वीलोन (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० के० चन्द्रन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/126/80(15)]

ORDER

S.O. 2188.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P. K. Chandran, Plavila Veedu, Kottyaim P.O., Quilon (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 126-Chathannoor Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commissin hereby declares the said Shri P.K. Chandran to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/126/80(15)]

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 1980

का० आ० 2189.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 3-बोब्बिली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रामभद्र राजू पाकालपति एस० यू० सी० आई० पार्टी कार्यालय, टोपाकला स्ट्रीट, विजयानगरम-2 (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामभद्र राजू पाकालपति को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आं० प्र०-लो० स०/3/80(10)]

ORDER

New Delhi, the 21st July, 1980

S.O. 2189.—Whereas the Election Commission is statisfied that Shri Ramabhadra Raju Pakalapati, S.U.C.I. Party Office, Topakula Street, Vizianagaram (Andhra Pradesh), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 3-B Bobbili Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramabhadra Raju Pakalapati to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliment or of the Legistive Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

By Order,

[No. AP-HP/3/80(10)]

आदेश

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 1980

का० आ० 2190.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 26-पेण्डुरथी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार

श्री येराकय्यानायडू टटिकोण्डा, नाडुपुरु, तालुक-विशाखापतनम, जिला विशाखापतनम (आन्ध्र प्रदेश) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार, ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री येराकय्यानायडू टटिकोण्डा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० आं० प्र० वि० स०/26/80(उप) (II)]

ORDER

New Delhi, the 22nd July, 1980

S.O. 2190.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yerakayyanaidu Tatikonda, Nadupuru, Visakhapatnam Taluk, District Visakhapatnam (Andhra Pradesh), a contesting candidate for bye-election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in January, 1980 from 26-Pendurthi Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yerakayyanaidu Tatikonda to be disqualified for being chosen as,and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[N. AP-LA/26/80(Bye)(11)]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1980

का०आ० 2191.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 58-त्रिचूर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भारथन थमपुरम, वलियाकोविलाकम, त्रिचूर-1 (केरल) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भारथन थमपुरम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/58/80(20)]

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1980

S.O. 2191.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bharathan Thampuram, Valiyakovilakam, Trichur-1 (Kerala), a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 58-Trichur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules, made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bharathan Thampuram to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/58/80(20]

आदेश

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1980

का० आ० 2192.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए केरल विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 63-इरिन्जालाकुडा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० एन० पिशारोडि, पुथेनविशारोथ, मापरानम, डाक० मडाईकानम, केरल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० एन० पिशारोडि को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० केरल-वि० स०/63/80(21)]

आदेश से,

धर्मवीर, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 30th July, 1980

S.O. 2192.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P.N. Pisharody, Puthenpisharoth, Mapranam, P.O. Madaikanam, Kerala, a contesting candidate for general election to the Kerala Legislative Assembly held in January, 1980 from 63-Irinjalakuda Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P.N. Pisharody to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KL-LA/63/80(21)]

By order,

DHARAM VIR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1980

का० आ० 2193.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 4-श्रीपेरुम्बुदुर (अ० जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टी० वरदाराजन, ग्राम व डाक० सोरायनपलायम, तालुक-तिरुवल्लुर, जिला-चेंगलपट्टु (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री टी० वरदाराजन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त० ना०-लो० स०/4/80(2)]

ORDER

New Delhi, the 18th July, 1980

S.O.2193.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri T. Varadarajan, soarayanpalayam Village and Post, Tiruvallur Taluk, Chengalpattu District, (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 4-Sriperumbudur (SC) parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the matter as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri T. Viradarajan, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/4/80(2)]

आदेश

का० आ० 2194.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 26-करुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पी० एम ईलामारन, कृष्णापुरम, सविनथीपट्टी (डाक), (वाया) थोट्टीयम, जिला तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पी० एम० ईलामारन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०-लो० स०/26/80(3)]

ORDER

S.O 2194.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri P.M. Elamaran, Krishnapuram, Sevinthipatti (P.O.), (Via) Thottiam, District Tiruchirappalli, (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 26-Karur parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri P.M. Elamaran to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/26/80(3)]

आदेश

का० आ० 2195.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 28-पैरम्बलूर (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री के० कुमारावेल, सुपुत्र कुलनडाइवेल, मलाईकाडाई, चेट्टीकुलम डाक०, पेरम्बलूर तालुक (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण, अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री के० एम० कुमारावेल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त० ना०-लो० स०/28/80(4)]

ORDER

S.O. 2195.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri K. Kumaravel, S/o Kulandaivel, Malaikadai, Chettikulam Post, Perambalur Taluk (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 28-Perambalur (SC) Parliamentry constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri K. M. Kumaravel, to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/28/80(4)]

आदेश

का० आ० 2196.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 36-तिरुनेलवेली संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री डेविड नाडार सुपुत्र गनानागरुपाथन नाडार, 39, कुल्यानकारिसाल (वाया) पुडुकोट्टाई, टुटिकोरिन तालुक (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री डेविड नाडार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त० ना०-लो० स० 36/80(5)]

ORDER

S.O. 2196.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri David Nadar S/o Gnanagarupathan Nadar, 39, Kulayankarisal (via) Pudukottai, Tuticorin Taluk (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 36-Tirunelveli Parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commissin hereby declares the said Shri David Nadar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/36/80(5)]

का० आ० 2197—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-वालपराई (अ० जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जैम्स उर्फ के० कुमारस्वामी, मार्फत पी० जयचन्द्र बोस, उ० नि० पुलिस, मडाथुकुलम, उडमाल्पेट तालुक, कोयम्बटूर जिला, तमिलनाडु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जैम्स उर्फ के० कुमारस्वामी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०वि० स०/110/77(62)]

ORDER

S.O. 2197.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri James alias K. Kumaraswamy, C/o P. Jayachandra Bose, S.I. of Police Madathukulam, Udamalpet Taluk, Coimbatore District (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in June, 1977 from 110-Valparai (SC) Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri James alias K. Kumaraswamy to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/110/77(62)]

आदेश

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1980

का०आ० 2198.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-वेल्लोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जी० कमलाकानन, ग्राम व डाक० उनई, तालुक वेल्लोर, जिला उत्तरी अर्काट (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जी० कमलाकानन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०—लो० स०/7/80(6)]

ORDER

New Delhi, the 19th July, 1980

S.O. 2198.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri G. Kamalakanan, Unai Village and Post, Vellore Taluk, North Arcot District,(Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 7-Vellore Parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And Whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri G. Kamalakanan to be disqualified for being chosen as, and for being a member either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/7/80(6)]

आदेश

का०आ० 2199.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 11—कुड्डालोर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए० रामालिंगम, 99-ए/2, मेन रोड, पुदूपालायाम, कुड्डालोर-1 (तमिलनाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ए० रामालिंगम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०ना०—लो०स०/11/80(7)]

ORDER

S.O. 2199.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Ramalingam, 99-A/2, Main Road, Pudupalayam, Cuddalore-1 (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 11-Cuddalore parliamentary constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder :

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason of justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10- A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Ramalingam to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-HP/11/80/(7)]

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1980

का०आ० 2200.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए तमिलनाडु के लिए उप-साधारण निर्वाचन के लिए 91–पानामारातुपट्टी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री एस० आई० राजकुमार, सुपुत्र इरुलाप्पन, पो० आयोथियापटनम, ता० सलेम (तमिलनाडु), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और, यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री एस०आई० राजकुमार को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० त०न०-वि०स०/91/80(उप) (8)]

एस० सी० जैन, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 4th Agust, 1980

S.O. 2200.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri S.I. Rajkumar S/o Irulappan, Ayothiapattinam Post, Salem Taluk (Tamil Nadu), a contesting candidate for bye-election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in January, 1980 from 91-Panamarathupatty Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951 and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri S.I. Rajkumar to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/91/80(Bye) (8)]

S. C. JAIN, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1980

का०आ० 2201—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20–भीलवाड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री टीकम चन्द, नाथ द्वारा सराय, भीलवाड़ा (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री टीकम चन्द को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-लो०स०/20/80(3)]

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1980

S.O. 2201.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tikamchand, Nathdwara Sarai, Bhilwara (Rajasthan), a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 20 Bhilwara constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tikamchand to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ/HP/20/80(3)]

आदेश

का०आ० 2202.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20—भीलवाड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नन्द लाल, लढ़ा निवास, वकील कालोनी भीलवाड़ा (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, समयक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नन्द लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज० लो०स०/20/80(4)]

S.O. 2202 :— Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nand Lal, Ladha Niwas, Vakil Colony, Bhilwara (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980, from 20-Bhilwara constituency, has failed to lodge any account of his election expences as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Conmission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nand Lal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ/HP/20/80(4)]

आदेश

का०आ० 2203.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए

20—भीलवाड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भोलाराम, मकान नं० 30, वार्ड नं० 12, भोपाल गंज, भीलवाड़ा, (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भोलाराम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०लो०स०/20/80 (5)]

ORDER

S.O. 2203 :— Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhola Ram, House No. 30, Ward No. 12, Bhopalganj, Bhilwara (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 20-Bhilwara constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhola Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ/HP/20/80(5)]

आदेश

का० आ० 2204.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 20-भीलवाड़ा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सत्यनारायण, वार्ड नं० 8, बनेड़ा, जिला—भीलवाड़ा (राजस्थान), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सत्यनारायण को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० राज०-लो०स०/20/80(6)]

ORDER

S.O. 2204 :— Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Satya Narain, Ward No. 8, Banera District, Bhilwara (Rajasthan) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 20-Bhilwara constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Satya Narain to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. RJ/HP/20/80(6)]

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1980

का० आ० 2205.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 33-शाजापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बिहारी लाल, 19 हटेसिंह गोयल मार्ग, देवास, मध्य प्रदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बिहारी लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र०-लो०स०/33/80(1)]

आदेश से,

ओ० ना० नागर, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1980

S.O. 2205 :— Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bihari Lal, 19 Hate Singh Goyal Marg, Dewas, Madhya Pradesh, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 33 Shajapur constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bihari Lal to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-HP/33/80/(1)]

By Order,

O. N. NAGAR, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 1979

आय-कर

का०आ० 2206.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि विहित प्राधिकारी, अर्थात्, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली ने निम्नलिखित संस्था को आय-कर नियम, 1962 के नियम 6(4) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) के प्रयोजनों के लिए अन्य प्राकृतिक या आनुप्रयोगिक विज्ञान के क्षेत्र में "संगठन" प्रवर्ग के अधीन निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदित किया है, अर्थात्:—

(1) यह कि बिड़ला पुरातत्व और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद प्राकृतिक या आनुप्रयोगिक (कृषि/पशुपालन/मात्स्यकी और औषधि से भिन्न) विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों का हिसाब पृथक से रखेगा ।

(2) उक्त संस्थान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान संबन्धी क्रियाकलापों का एक वार्षिक विवरण विहित प्राधिकारी को प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक ऐसे प्ररूपों में प्रस्तुत करेगा जो इस प्रयोजन के लिए अधिकथित किए जाएं और उसे सूचित किए जाएं ।

संस्था

बिड़ला पुरातत्व और सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।

यह अधिसूचना 1-1-79 से 31-12-1981 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 3083 (फा०सं० 203/72/79 आई०टी०ए० II]
जे० पी० शर्मा, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th December, 19?9

INCOME TAX

S. O. 2206.—It is hereby notified for general information that the institution mentioned below has been approved by the Secretary, the Department of Science & Technology, New Delhi, the prescribed authority for the purposes of clause (ii) of sub-section (1) of Section 35 of the Income-tax Act, 1961 read with Rule 6(iv) of the Income-tax Rules, 1962 under the category "Association", in the area of other natural or applied sciences, subject to the following conditions:—

(i) that the Birla Archaeological & Cultural Research Institute, Hyderabad, will maintain a separate account of the sums received by it for scientific research in the field of natural or applied sciences other than agriculture/animal husbandry/fisheries and medicines.

(ii) That the said Institute will furnish the annual return of its scientific research activities to the prescribed authority for every financial year in such, forms as may be laid down and intimated to them for this purpose, by 30th April, each year.

INSTITUTION

Birla Archaeological & Cultural Research Institute, Hyderabad.

This notification is effective for a period of 3 years from 1-1-79 to 31-12-1981.

[No. 3083 (F. No. 203/72/79-ITA.II]
J. P. SHARMA, Director

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1980

का०आ० 2207.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उपनियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश करते हैं कि भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) की अधिसूचना सं० 19/17/74–ए वी डी तारीख 4 नवम्बर, 1974 के निम्नलिखित और संशोधन किए जाएंगे अर्थात्:—

1. उक्त अधिसूचना में,—

(i) "वर्ग II" शब्द और अंक, जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "समूह ख" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "वर्ग III" शब्द और अंक, जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "समूह ग" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) "वर्ग IV" शब्द और अंक, जहां कहीं भी वे आते हैं, के स्थान पर "समूह घ" शब्द और अक्षर रखे जाएंगे।

2. विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:—

"अनुसूची

भाग I—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख'

क्रम सं०	पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और वे शास्तियां जो वह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में मद संख्याओं के प्रति निर्देश से)		अपील प्राधिकारी
			अनुशासनिक प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5	6
1.	प्रवर्तन निदेशालय में समूह 'ख' पद	प्रवर्तन निदेशक और जब प्रवर्तन निदेशक का पद रिक्त है तब विशेष प्रवर्तन निदेशक या अपर प्रवर्तन निदेशक	प्रवर्तन निदेशक और जब प्रवर्तन निदेशक का पद रिक्त है तब विशेष प्रवर्तन निदेशक या अपर प्रवर्तन निदेशक/	सभी	सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग,
			विशेष प्रवर्तन निदेशक/अपर प्रवर्तन निदेशक	(i) से (iv)	प्रवर्तन निदेशक

भाग II—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'

2.	प्रवर्तन निदेशालय में समूह 'ग' पद	उपनिदेशक प्रवर्तन	उपनिदेशक प्रवर्तन	सभी	निदेशक प्रवर्तन
			सहायक निदेशक प्रवर्तन	(i) से (iv)	उप निदेशक प्रवर्तन

भाग III—साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'घ'

3.	प्रवर्तन निदेशालय में समूह 'घ' पद	उपनिदेशक प्रवर्तन	उपनिदेशक प्रवर्तन	सभी	निदेशक प्रवर्तन
			सहायक निदेशक प्रवर्तन/मुख्य प्रवर्तन अधिकारी जो उपकार्यालय/एकक का भारसाधक है।	(i) से (iv)	उपनिदेशक प्रवर्तन"

[फा०सं० 2/4/80–प्रशा०/ए (सी)]
बी० के० अरोड़ा, डेस्क आफिसर

New Delhi, the 18th August, 1980

S. O. 2207.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9, clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, the President hereby directs that the following further amendments shall be made in the notification of the Government of India in the Cabinet Secretariat (Department of Personnel and Administrative Reforms) No. 19/17/74-AVD-IV, dated the 4th November, 1974, namely:—

1. In the said notification:—

(i) for the word and figure "Class II", wherever they occur, the word and letter "Group B" shall be substituted;

(ii) for the word and figures "Class III", wherever they occur, the word and letter "Group C" shall be substituted;

(iii) for the word and figure "Class IV", wherever they occur, the word and letter "Group D" shall be substituted.

2. For the existing Schedule, the following Schedule shall be substituted:—

"SCHEDULE

Part I—General Central Service Group 'B'

S. No.	Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties which it may impose (with reference to item Nos. in rule 11).		Appellate Authority
			Disciplinary Authority	Penalties	
1	2	3	4	5	6
1.	Group 'B' posts in the Directorate of Enforcement.	Director of Enforcement and when the post of Director of Enforcement is vacant, Special Director of Enforcement or Additional Director of Enforcement.	Director of Enforcement and when the post of Director of Enforcement is vacant, Special Director of Enforcement or Additional Director of Enforcement.	All	Secretary, Ministry of Finance Department of Revenue.
			Special Director of Enforcement /Additional Director of Enforcement	(i) to (iv)	Director of Enforcement.
		Part II—General Central Service Group 'C'			
2.	Group 'C' posts in the Directorate of Enforcement.	Deputy Director of Enforcement.	Deputy Director of Enforcement.	All	Director of Enforcement.
			Assistant Director of Enforcement.	(i) to (iv)	Deputy Director of Enforcement.
		Part III—General Central Service Group 'D'			
3.	Group 'D' posts in the Enforcement Directorate.	Deputy Director of Enforcement.	Deputy Director of Enforcement.	All	Director of Enforcement.
			Assistant Director of Enforcement/Chief Enforcement Officer who is incharge of sub-office/ Unit.	(i) to (iv)	Deputy Director of Enforcement."

[F. No. 2/4/80-Ad. IA (C)]

B. K. ARORA, Desk Officer,

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

का०आ० 2208.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री जी०पी० श्रीवास्तव को इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 23-8-1980 से प्रारम्भ होकर 22-8 1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री जी०पी० श्रीवास्तव, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[संख्या एफ० 1-5/80-आर०आर०बी०]

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 22nd August, 1980

S.O. 2208.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri G.P. Srivastava as the Chairman of the Allahabad Kshetriya Gramin Bank, Allahabad and specifies the period commencing on the 23rd August, 1980 and ending with the 22nd August, 1983 as the period for which the said Shri G.P. Srivastava shall hold office as such Chairman.

[No. F.1-5/80-RRB]

नई दिल्ली 23 अगस्त, 1980

का० आ० 2209.—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा श्री वी०पी० सिंह को प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 25-8-1980 से प्रारम्भ होकर 24-8-1983 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री वी०पी० सिंह, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे ।

[सख्या एफ० 1-6/80-आर०आर० बी०]
इन्द्रानी सेन, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd August, 1980

S.O. 2209.—In exercise of the powers, conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government hereby appoints Shri V.P. Singh as the Chairman of the Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank, Pratapgarh and specifies the period commencing on the 25-8-1980 and ending with the 24-8-1983 as the period for which the said Shri V.P. Singh shall hold office as such Chairman.

[No. F. 1-6/80-RRB]
INDRANI SEN, Under Secy.

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय, मदुरई-2

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क

मदुरई 28 जुलाई, 1980

का० आ० 2210.—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, आर० जयरामन, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, मदुरई, एतद्द्वारा इस समाहर्तालय के प्रभागीय सहायक समाहर्ताओं को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमावली, 1944 के खण्ड (VI ए) (डी) के नियम 56ए के उप नियम 3 के अन्तर्गत समाहर्ता में निहित समाहर्ता की शक्तियों को अपने संबन्धित अधिकार क्षेत्र में जो निर्माणकर्ता ता० 1-8-1980 के पूर्व तक नियम 8 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना द्वारा शुल्क परिसाधित उत्पादन शुल्क माल के निर्माण में समायोजना कार्यविधि के अन्तर्गत पदार्थ एवं साधकों को उपयोग करने की सुविधा उठा रहे हैं, काम में नहीं लायी गई जमा स्टाक एवं शुल्क प्रदत्त पदार्थ आदि स्टॉक में पड़ी हुई हैं, अपनी लेखा में प्रपत्र आर०जी० 23 में बदली करने की अनुमति देने के अधिकार को प्रदत्त करता हूं ।

[अधिसूचना सं० 3/80/फाइल सी०सं० IV/16/40/80-के०उ०शु० 2 से जारी]
आर० जयरामन, समाहर्ता

Office of the Collector of Ce ,tral Excise, Madurai-2

CENTRAL EXCISE

Madurai 28 July 1980

S. O. 2210.—In exercise of the powers conferred upon me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I. R. Jayaraman, Collector of Central Excise, Madurai hereby authorise Assistant Collectors of Central Excise incharge of the Divisions to exercise within their respective jurisdiction, the powers of the Collector under clause (VI a) (d) of sub-rule 3 of rule 56A of Central Excise Rules, 1944 for permitting a manufacturer who had been immediately, before 1-8-80 availing the set off procedure on materials or component parts used in the manufacture of dutiable finished excisable goods by a notification issued under Rule 8, to transfer the amount of unutilised credit and the stock of duty paid materials etc., lying in stock to his account in form R.G. 23.

[Notification No. 3/80/Issued from file C. No. IV/16/40/80-CX.2]
R. JAYARAMAN, Collector

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

चंडीगढ़, 23 जुलाई, 1980

का० आ० 2211.—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत मुझ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, के० के० द्विवेदी, समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चंडीगढ़ एतद्द्वारा, सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क को उनके संबन्धित क्षेत्राधिकार में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क (यथा संशोधित) के उपनियम (3) के उपखंड (घ) के अन्तर्गत समाहर्ता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूं ।

[अधिसूचना सं० 2/के०उ०शु०/80 सी०सं० IV(16) 8-के०उ०शु०टे०/80/भाग-II/8790-899]
के०के० द्विवेदी, समाहर्ता

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE CHANDIGARH

CENTRAL EXCISE

Chandigarh, the 23rd July, 1980

S.O. 2211.—In exercise of the powers conferred upon me under rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, K. K. Dwivedi, Collector of Central Excise, Chandigarh hereby authorise the Assistant Collector of Central Excise to exercise the powers vested in the Collector under sub cluase (d) of sub-rule (3) of rule 56A (as amended) of the Central Excise Rules, 1944, within his respective jurisdiction.

[Notification No. 2-CE/80/C. No. IV-(16) 8-Tech/80/Pt. II/56147 to 56354.]
K. K. DWIVEDI, Collector

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980

का० आ० 2212.—केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वैक्यूम फलास्क से संबंधित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 1616 तारीख 7 मई, 1968 का नीचे विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाए,

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रयोजन के लिए नीचे विनिर्दिष्ट प्रस्ताव बनाए हैं और उन्हें निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उपनियम (2) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद को भेज दिया है,

अतः उक्त नियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त प्रस्तावों को उन व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित करती है जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है ।

सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्तावों के बारे में आक्षेप या सुझाव देने की इच्छुक व्यक्ति यह उन्हें इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् "वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर" 14/1 बी०, एजरा स्ट्रीट (सातवीं मंजिल) कलकत्ता -1 को भेज सकता है।

प्रस्ताव

भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 1616 तारीख 7 मई, 1968 का निम्न रूप से संशोधन किया जाएगा, अर्थात् :—

"क. रिफिलों के लिए विनिर्देश" शीर्षक के अंतर्गत अधिसूचना सं० का० आ० 1616 तारीख 7 मई, 1968 के उपाबंध में स्तम्भ 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :

'6. उष्मा धारण क्षमता निम्न रूप से परीक्षित की जाएगी :—

95° सें० ग्रेड पर गर्म किया हुआ जल जब रिफिल में रखा जाता है (निम्न रीति से विनिर्दिष्ट) तो नीचे वर्णित से कम नहीं होगा :—

रिफिल का प्रकार	प्राप्त तापमान कम नहीं होगा		पांच घंटों के परीक्षण के पश्चात् स्तम्भ (2) से हर तीसरा
	एक घंटे के परीक्षण	चौबिस घंटों के परीक्षण के पश्चात्	
	(1)	(2)	(3)
(1) $\frac{1}{2}$ लिटर से कम अंकित धारिता का संकीर्ण मुख (आंतरिक मुख का व्यास 45 मिली लिटर तक होगा)	91° सें०ग्रे०	50° सें०ग्रे०	78° सें०ग्रे०
(2) $\frac{1}{2}$ लिटर तथा अधिक अंकित धारिता का चौड़ा मुख (आंतरिक मुख का व्यास 45 मि० मीटर से ऊपर)	85° सें० ग्रे०	42° सें० ग्रे०	70° सें० ग्रे०
(3) 250 मि० लि० अंकित धारिता (आंतरिक मुख का व्यास 30 मि० लि० मीटर तक होगा)।	85° सें० ग्रे०	40° सें० ग्रे०	70° सें० ग्रे०
(4) 250 मि० लि० लिटर अंकित धारिता (आंतरिक मुख व्यास 30 मि० लि० मीटर से किन्तु 45 मिली मीटर से कम)	88° सें० ग्रे०	38° सें० ग्रे०	68° सें० ग्रे०
(5) प्रयोग के लिए आशयित रिफिल तथा अन्य प्रकार जैसे, गिलास, बर्फ के कटोरे आदि :—	निर्यातकर्ता द्वारा घोषित के अनुसार		

प्रक्रिया : उबलते हुए जल में रिफिल खंगालना, जहां तक संभव हो अधिक से अधिक जल निकालना, शीघ्र ही 95° सें० ग्रे० पर उबलता जल इसके गले तक भर दें, डाट से मुंह बंद कर दें और समय नोट कर लें।

[सं० 6 (29)/79- नि० नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 6th September, 1980.

S.O. 2212.—Whereas the Central Government is of opinion that in exercise of the powers conferred by section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), it is necessary and expedient to further amend the Notification of the Government of India in late Ministry of Commerce No. S.O. 1616, dated the 7th May, 1968 relating to vacuum flasks in the manner specified below for the development of the Export Trade of India;

And whereas the Central Government has formulated the proposals specified below for the said purpose and has forwarded the same to the Export Inspection Council as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and inspection,), Rules 1964;

Now, therefore, in pursuance of the said rule, the Central Government hereby publishes the said proposals for the information of the public likely to be effected thereby.

2. Notice is hereby given that any person desiring to forward any objection or suggestion with respect to the said proposals may forward the same within 45 days from the date of publication of this notification on the Official Gazette to the Export Inspection Council "World Trade Centre", 14/1B, Ezra street (7th Floor) Calcutta-1.

PROPOSALS

The order of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S. O. 1616, dated the 7th May, 1968 shall be further amended as follows, namely:—

In the Annexure to the notification No. S. O. 1616 dated 7th May, 1968 under the heading "A specifications for refills" for clause 6, the following shall be substituted, namely:—

The heat retentions capacity shall be tested as follows:

The temperature of water heated to 95° C and when kept in refills (in the manner specified below) shall not be less than these indicated below :—

Types of refills	Temperature attained, net less than		After five hrs. test, alternative to Column (2)
	After one hour test	After 24 hours test	
	(1)	(2)	(3)
(1) Narrow mouth of nominal-capacity not less than $\frac{1}{2}$ litre (internal mouth dia meter upto 45 mm)	91°C	50°C	78°C
(2) Wide mouth of nominal capacity of $\frac{1}{2}$ litre and above (internal) mouth diameter above 45 mm)	85°C	42°C	70°C
(3) 250ml. nominal capacity (internal mouth diameter upto 30 mm)	85°C	40°C	70°C
(4) 250ml. nominal capacity (internal mouth diameter above 30 mm but below 45 mm)	88°C	38°C	68°C
(5) other types and refills meant for use as tumblers ice bowls, etc.	As declared by the exporters.		

Procedure :—Rinse the refills with boiling water, draining out as much of water as possible. Quickly fill it up to the neck with water at 95°C, close the mouth with the stopper and note the time".

[No. 6 (29)/79-EI & EP)]

C. B. KUKRETI, Jt. Director.

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980

का० आ० 2213—केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 2908 तारीख 5 अगस्त 1971 को अधिक्रांत करते हुए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धनिया का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1980 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है,

(ग) "निरीक्षण अधिकारी" से धनिया के निरीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 7 के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता-प्राप्त है,

(घ) "प्राधिकृत पैकर" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इन नियमों के अधीन विहित श्रेणी मानक और प्रक्रिया के अनुसार वस्तुओं का श्रेणीकरण और एग्मार्क करने के लिए प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है,

(ङ) "प्राधिकरण का प्रमाण पत्र" धनिया का श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1964 के अनुसार धनिया का श्रेणीकरण करने का इच्छुक व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय को कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या उसके द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है :

(च) "धनिया" से भारत में उत्पादित कोरिन्ड्रम सेटिवम एल (साबुत या पिसा हुआ) के पौधों से प्राप्त धनिया अभिप्रेत है ।

3. निरीक्षण का आधार:—निर्यात के लिए आशयित धनियों का निरिक्षण इस दृष्टि से किया जाएगा कि वह का० आ० सं० 2907 तारीख 5 अगस्त, 1971 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मानक विनिर्देशों के अनुरूप है ।

4. निरीक्षण की प्रक्रिया :—(1) निर्यात के लिए आशयित धनिया कृषि विपणन सलाहकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए निदेशों के अनुसार केवल प्राधिकृत पैकर द्वारा ही श्रेणीकृत और पैक किया जाएगा ।

(2) प्राधिकृत पैकर का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह धनिया का श्रेणीकरण करने और नमूना लिए जाने का प्रबंध करे तथा परीक्षा आदि के लिए उचित सुविधाएं भी प्रदान करे जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा विहित की जाए ।

(3) धनिया का निर्यात करने का इच्छुक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा निर्धारित ब्यौरों सहित निकटतम निरीक्षण अधिकारी को लिखित सूचना देगा ताकि वह नियम 3 के अनुसार धनिया के लाटों का श्रेणीकरण और चिह्नांकन कर सके ।

(4) उप-नियम 3 के अधीन प्रत्येक सूचना :—

(क) निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित पैकिंग केन्द्रों पर श्रेणीकरण और चिन्हांकन कम करने से कम से कम दो दिन पहले दी जाएगी ;

(ख) अन्य स्थानों पर, जो निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालय पर स्थित नहीं है, श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने से कम से कम 10 दिन पहले दी जाएगी ।

(5) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षण अधिकारी धनिया के परेषणों का निरीक्षण कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार इस दृष्टि से करेगा कि वह नियम 3 में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त विनिर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

(6) यदि निरीक्षण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि परेषण नियम 3 में निर्दिष्ट विनिर्देशों के अनुसार है तो वह कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार धनिया के डिब्बों या पैकेजों पर चिपकाने के लिए एग्मार्क लेबल जारी करेगा :

परन्तु यदि निरीक्षण अधिकारी का इस प्रकार का समाधान नहीं होता है तो वह उक्त एग्मार्क लेबलों को जारी करने से इंकार कर देगा और प्राधिकृत पैकर को तथ्य की उसके कारणों सहित लिखित सूचना देगा ।

(7) धनिया के श्रेणीकृत और लेबल लगे हुए परेषणों का निर्यात करने का इच्छुक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा नियम 3 के अनुसार विहित ब्यौरों सहित इसकी निर्यात योग्यता प्रमाण-स्वरूप श्रेणीकरण के प्रमाण-पत्र के लिए निरीक्षण अधिकारी के निकटतम कार्यालय में आवेदन करेगा ताकि वह ऐसा प्रमाण-पत्र जारी कर सके ।

(8) उप-नियम (7) के अधीन प्रत्येक आवेदन पत्र :—

(क) उप-नियम 7 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालयों पर पैकिंग केन्द्रों पर जारी करने से कम से कम दो दिन पहले दिया जाएगा ।

(ख) उप-नियम 7 में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र अन्य स्थानों पर जो निरीक्षण अधिकारी के मुख्यालयों पर स्थित नहीं है जारी करने से कम से कम 3 दिन पहले दिया जाएगा ।

(9) उप-नियम (7) में निर्दिष्ट आवेदन प्राप्त होने पर निरीक्षण अधिकारी धनिया के श्रेणीकृत परेषणों का निरीक्षण करेगा और प्रत्येक श्रेणीकृत लॉट के लिए एक पृथक जांच नमूना लेगा ।

(10) यदि उप-नियम (7) में निर्दिष्ट परेषणों के नमूनों की जांच और जांच नमूने के परीक्षण के पश्चात् निरीक्षण अधिकारी का समाधान हो जाता है कि निर्धारित श्रेणी मान्यताप्राप्त विनिर्देशों के अनुसार है तो वह ऐसे परेषणों के संबंध में निर्यात योग्यता के प्रमाण-स्वरूप श्रेणीकरण का प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

परन्तु यदि निरीक्षण अधिकारी का इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह प्राधिकृत पैकर को तुरन्त तथ्य को उसके कारणों सहित लिखित सूचना देगा और श्रेणीकरण का उक्त प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा ।

5 निरीक्षण के स्थान :—इन नियमों के प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक निरीक्षण प्राधिकरण के प्रमाण-पत्र में उल्लिखित प्राधिकृत परिसरों पर किया जाएगा और जांच निरीक्षण या जांच नमूना निर्यात से पूर्व किसी भी स्थान पर कृषि विपणन सलाहकार या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

6. एग्मार्क लेबलों के प्रभारों का संदाय :—प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाह द्वारा निर्दिष्ट रीति से एग्मार्क लेबलों को ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो भारत सरकार द्वारा समय पर अधिसूचित किए जाते हैं।

7. परीक्षण या जांच नमूनों का पुनः परीक्षण :—(1) यदि पैकर निरीक्षण अधिकारी के परिणामों से संतुष्ट नहीं है तो वह परेषण के पुनः परीक्षण करने का प्रबंध करने के लिए संबंधित निरीक्षण अधिकारी से लिखित अनुरोध करने का हकदार होगा और उसके पश्चात् एक या अधिक परीक्षण नमूने या जांच नमूने लिए जाएंगे और उनका परीक्षण किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन विश्लेषण के परिणामों का पूर्ववर्ती नमूने के साथ औसत निकाला जाएगा और औसतन परिणाम श्रेणी, अभिधानों का निर्धारण करने के लिए किया जाएगा।

8. अपील :—यदि कोई प्राधिकृत पैकर निरीक्षण अधिकारी द्वारा नियम 4 के उप-नियम (7) या उप-नियम (10) के अधीन परेषण के श्रेणीकरण करने या प्रमाण-पत्र जारी करने से इंकार से व्यथित है तो वह कृषि विपणन सलाहकार को जो उसके द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में उसके विवाद के संबंध में सलाह देने के लिए सलाहकार पैनल का गठन कर सकता है अपना विषय भेजने के लिए ठीक अगले कार्य दिवस को सांय 5 बजे तक लिखित रूप में निरीक्षण अधिकारी से लिखित प्रार्थना कर सकता है। कृषि विपणन सलाहकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

[सं० 1 (27)/73-नि०नि० तथा नि० उ०]

सी० बी० कुकरेती, संयुक्त निदेशक

New Delhi, the 6th September, 1980

S.O. 2213.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the late Ministry of Foreign Trade No. S.O. 2908 dated the 5th August, 1971, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Export of Coriander (Quality Control and Inspection) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India ;

(c) "Inspecting Officer" means the officer authorised by the Agricultural Marketing Adviser for inspection of Coriander recognised as the Agency under section 7 of the Act ;

(d)"Authorised Packer" means a person or a body of persons who has been granted a certification of authorisation by the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India, for getting the commodity graded Agmarked in accordance with the grade standard and procedure prescribed under the rules ;

(e) "Certification of Authorisation" means the certificate issued by the Agricultural Marketing Adviser or any other officer authorised in this behalf to a person or body of persons desirous of grading Coriander as per the Coriander Grading and Marking Rules, 1964;

(f) "Coriander" means the Coriander obtained from plant Coriandrum sativam L (Whole or powdered) produced in India.

3. Basis of Inspection.—Inspection of Coriander intended for export shall be carried out with a view to seeing that the same conforms to the standard specifications, recognised by the Central Government under S.O. No. 2907, dated the 5th August, 1971.

4. Procedure of Inspection.—(1) Coriander meant for export shall be graded and packed only by the authorised packer in accordance with the instructions issued in this behalf by the Agricultural Marketing Adviser.

(2) It shall be the responsibility of the authorised packer to make such arrangements for grading and sampling of Coriander and also provide requisite facilities for testing etc. as may be prescribed by the Agricultural Marketing Adviser.

(3) An authorised packer intending to export Coriander shall give intimation in writing along with such details as may be prescribed by the Agricultural Marketng Adviser to the nearest Inspecting Officer to enable him to grade and mark Coriander lots in accordance with rule 3.

(4) Every intimation under sub-rule (3) shall be given.—(a) not less than 2 days before the grading and marking is to be carried out at the packing centres situated at the Headquarters of the Inspecting Officers;

(b) not less than 10 days before the grading and marking is to carried out at the places, which are not situated at the Headquarters of the Inspecting Officers.

(5) On receipt of the intimation referred to in sub-rule (3), the Inspecting Officer shall inspect the consignments of Coriander as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser with a view to seeing that the same complies with the requirements of the recognised specifications referred to in rule 3.

(6) The Inspecting Officer shall issue Agmark labels for affixing the same on the containers or packages of Coriander as per instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser in case he is satisfied that the consignment(s) is as per specifications referred to in rule 3 :

Provided that if the Inspecting Officer is not so satisfied be shall refuse to issue the said Agmark labels and convey the fact immediately in writing to the authorised packer along with the reasons therefor.

(7) An authorised packer intending to export the graded and labelled consignments of Coriander shall apply to the nearest office of the Inspecting Officer for a certificate of grading in token of its export worthiness in writing along with such details as prescribed by the Agricultural Marketing Adviser in accordance with rule 3 to enable him to issue such certificate.

(8) Every application under sub-rule (7) shall be given :—

(a) not less than two days before the certificate, referred to in sub-rule (7) is to be issued at the packing centres situated at the Headquarters of the Inspecting Officer ;

(b) not less than 3 days before the certificate referred to in sub-rule (7) is to be issued at other places, which are not situated at the Headquarters of the Inspecting Officer.

(9) On receipt of the application referred to in sub-rule (7) the Inspecting Officer shall inspect the graded consignments of Coriander and draw a separate check sample for each graded lot.

(10) If, after check sampling of the consignments referred to in sub-rule (7) and after examination of the check samples, the Inspecting Officer is satisfied that the grade assigned is as per recognised specifications, he shall issue a Certificate of Grading in respect of that consignment(s) in token of their exportworthiness :

Provided that if the Inspecting Officer is not so satisfied he shall immediately intimate the fact in writing to the authorised packer along with the reasons and shall not issue the said Certificate of Grading.

5. Places of inspection.—Initial inspection for the purpose of these rules shall be carried out at the authorised premises mentioned in the certificate of authorisation and check inspection or check sampling can be done by Agricultural Marketing Adviser or an Inspecting Officer authorised by him in this behalf at any place before export.

6. Payment of charges for Agmark labels.—The authorised packer shall pay the Agmark label charges which are notified by the Government of India from time to time, in the manner specified by the Agricultural Marketing Adviser.

7. Re-examination of the test or check samples.—(1) if the packer is not satisfied with the results of the Inspecting Officer,

he shall be entitled to request the concerned Inspecting Officer in writing for re-examination of the consignments and one more test samples or a check sample shall, thereafter, be withdrawn and tested.

(ii) The results of analysis under sub-rule (1) shall be averaged with those of the previous sample and average result shall be taken for determining the grade designation.

8. Appeal.—If any authorised packer is aggrieved by the refusal of the Inspecting Officer to grade a consignment or to issue a certificate under sub-rule (7) or sub-rule (10) of rule 4, he may request the Inspecting Officer, in writing, latest by 5 p.m. on the following working day to prefer the matter to the Agricultural Marketing Adviser, who may constitute an Advisory panel to advise him on the dispute in accordance with the procedure laid down by him. The decision of the Agricultural Marketing Adviser shall be the final.

[No. 1(27)/73-FI&FP]

C. B. KUKRETI, Jt. Director

वाणिज्य मंत्रालय

(मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय)

रद्द करने का आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

का०आ० 2214.—सर्वश्री मुनावर शाह एंड संस, दि बुंद, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) को फिशिंग टेक्लेस और इसके उप साधित्रों के आयात के लिए केवल 10,000 रुपए मूल्य की लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए (लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण में मूल्य 10,600 रुपए तक की वृद्धि की गई) आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1434545/सी/एक्स एक्स/65/एच/77, दिनांक 19-11-1977 को प्रदान किया गया था। जो उसके जारी होने की तारीख से 24 मास के लिए वैध था। पार्टी ने उक्त आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति प्रदान करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि उससे मूल लाइसेंस खो गया है। पार्टी ने आयात व्यापार नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत आवश्यक शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार उक्त आयात लाइसेंस सीमा-शुल्क सदन विदेशी डाकघर, नई दिल्ली में पंजीकृत कराया गया था और आंशिक रूप में उपयोग में लाया गया था। लाइसेंस में केवल 4,579 रुपए की धनराशि शेष है। पार्टी ने लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति के बाद में मिल जाने अथवा पा जाने पर लाइसेंस प्राधिकारी को लौटाने का भी वचन दिया है।

2. मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रति खो गई है तथा निदेश देता हूं कि आवेदक को आयात लाइसेंस की सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि प्रति जारी की जानी चाहिए। आयात लाइसेंस की मूल सीमा-शुल्क प्रयोजन प्रति एतद्द्वारा रद्द की जाती है।

[मिसिल सं० 12/583/76-77/एम एल-1/559]

के० आर० धीर,

उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

(Office of the Chief Controller of Imports & Exports)

CANCELLATION ORDER

New Delhi, the 22nd August, 1980

S.O. 2214.—M/s. Munawar Shah and Sons, The Bund, Srinagar (J&K) were granted an import licence No. P/A/1434545/C/XX/65/H/77 dated 19-11-1977 for a.c.i.f. value of Rs. 10,000/- only (value enhanced to Rs. 10,600/- in the Exchange Control copy of the licence) for import of Fishing Tackles and its accessories valid for 24 months from the date of issue. The party has applied for grant of a Duplicate Custom Purpose copy for the aforesaid import licence on the ground that the original licence has been misplaced by them. The party has furnished necessary affidavit as per I.T.C. rules according to which the aforesaid import licence was registered with the Customs House Foreign Post, New Delhi and was utilised partly. The balance left in the licence is Rs. 4,579/- only. Party has also undertaken to return to the licensing authority the original Custom copy of the licence if the same is traced or found later on.

2. I am satisfied that the original Custom Purpose copy of the import licence has been misplaced and direct that a Duplicate Custom Purpose Copy of the import licence should be issued to the applicant. The original Custom Purpose Copy of the import licence is hereby cancelled.

[File No. 12/583/76-77/ML-I/559]

K.R. DHEER,

Dy. Chief Controller of Imports & Exports

For Chief Controller of Imports & Export

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1980

का० आ० 2215.—उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना संख्या 1526 जो तारीख 12-5-79 के राजपत्र के भाग 2 में पृष्ठ 1442 पर छपी थी, में आंशिक संशोधन करते हुए और सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकार की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का केन्द्रीय अधिनियम 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "बी०एच०ई०एल०, हरिद्वार के विधि विभाग के अध्यक्ष" की उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है। वह स्थानीय सीमाओं के अन्दर उक्त अधिनियम के द्वारा या के अधीन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जैसा तारीख 4-10-75 की पृष्ठ 3597 पर छपी अधिसूचना का०आ० संख्या 4296 की अनुसूची में परिभाषित किया गया है।

[फा० सं० 14-3/74-एच०ई०एम०]

एन० सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Heavy Industry)

New Delhi, the 20th August, 1980

S. O. 2215.—In partial modification of the Ministry of Industry's (Department of Heavy Industry) Notification No. 1526 on page 1442 in Part II of the Gazette dated 12-5-79 and in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971

(Central Act 40 of 1971), the Central Government hereby appoints'Head of the D r rtment of Law, BHEL, Hardwar, to be Estate Officer for the purposes of the said Act. He shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on the Estate Officer, by or under the said Act, within the local limits as defined in schedule to Notification S.O.No. 4296 on page 3597 dated 4-10-1975.

[F. No. 14-3/74-HEM]
N. SUBRAHMANYAM, Under Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

का० आ० 2216.—यतः, केन्द्र सरकार का यह अभिमत है कि भारत में खनिजों के संरक्षण और विकास के लिए यह आवश्यक है कि हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के कालबा, बनिहारी, दोचना और कालिया का नंगल गांवों के सभी क्षेत्रों में या क्षेत्रों के अन्तर्गत उपलब्ध किसी भी खनिज के बारे में यथासंभव सही-सही जानकारी एकत्र की जाए ।

और यतः, कथित गांवों के बारे में हरियाणा राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे स्वीकृत कर दिए गए हैं ।

अतः अब, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार हरियाणा राज्य सरकार से परामर्श के बाद सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले के कालबा, बनिहारी, दोचना और कालिया का नंगल ग्रामों की किसी भी जमीन में किसी भी खनिज की उपलब्धि के बारे में यथा-आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के प्रयोजन से, एतद्द्वारा, व्यापक खोज करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

[फाइल सं० 4(5)/80-खान-6]

प्रसन्न चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

New Delhi, the 12th August, 1980

S.O. 2216.—Whereas, the Central Govt. is of opinion that for the conservation and development of mineral in India it is necessary to collect as precise information as possible with regard to any mineral available in or under all the areas covered by village Kalbar Banihari, Dochana and Kalia Ka Nangal of District Mohindergarh, Haryana.

And whereas, in respect of the said villages, mining leases have been granted by the State Government of Haryana;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18A of the Mines and Minerals (Regulation and Development Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government after consultation with the State Govt. of Haryana, hereby authorises the Cement Corporation of India to carry out such detailed investigations for the purpose of obtaining such information with regard to the availability of any mineral as may be necessary in any land of the villages Kalba, Banihari, Dochana and Kalia Ka Nangal of District Mohindergarh, Haryana.

[File No. 4(5)/80-MVI]
PARSAN CHANDRA, Under Secy.

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पैट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

का० आ० 2217.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० 159 से जी० जी० एस०-6 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतदुपाबद्ध अनुसूचि में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, बडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करनेवाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

कूप नं० 159 से जी० जी० एस० VI तक पाइप लाइन बिछाने के लिए।

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कलोल

गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
छत्राल	323	0	03	00

[सं० 12016/36/80-प्रो०]

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

New Delhi, the 12 August, 1980

S.O. 2217.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from well No. 159 to GGS VI in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And Whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein :

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009;

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

Pipeline from Well No. 159 to G.G.S. VI

State : Gujarat District : Mehsana Taluka : Kalol

Village	Block No.	Hectare	Are	Centiare
Chhatral	323	0	03	00

[No. 12016/36/80 Prod.]

का० आ० 2218.—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप नं० झालोरा-4 से जी०जी०एस० झालोरा तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ;

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ;

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है :

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ;

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

झालोरा 4 से जी० जी० एस० झालोरा तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात जिला—मेहसाना तालुका—कडी

गांव	सर्वेक्षण नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टीयर
	364	0	10	20
झामलीयारा	365	0	16	35
	350	0	10	95
	337	0	07	80
	342	0	06	00
	339	0	09	00
	340	0	12	90
	262	0	24	45
	261	0	11	40
	256	0	02	70
	257	0	14	85
	237	0	09	68
	238	0	01	20
	239	0	11	55
	कार्ट ट्रेक	0	02	62
	125/5	0	03	90
	242	0	05	10
	121	0	05	40
	123/1	0	03	50
	123/2	0	03	60
	155 और 154	01	04	10
	142/1	0	03	15
	151	0	04	20

[सं० 12016/35/80-प्रो०]

S.O. 2218.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from Jhalora-4 to GGS Jhalora in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in and) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction and Maintenance Division, Marakpura Road, Vadodara-390009 ;

And every person making such an obection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

PIPELINE FROM JHALORA—4 TO G.G.S. JHALORA

STATE : Gujarat	DISTRICT : Mehsana	TALUKA : Kadi		
Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
AMALIYARA	364	0	10	20
	365	0	16	35
	350	0	10	95
	337	0	07	80
	342	0	06	00
	339	0	09	00
	340	0	12	90
	262	0	24	45
	261	0	11	40
	256	0	02	70
	257	0	14	85
	237	0	09	68
	238	0	01	20
	239	0	11	55
	CART TRACK	0	02	62
	125/5	0	03	90
	242	0	05	10
	121	0	05	40
	123/1	0	03	50
	123/2	0	03	60
	155 & 154	01	04	10
	142/1	0	03	15
	151	0	04	20

[No. 12016/35/80—Prod]

का० आ० 2219.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का०आ० सं० 258 तारीख 2-1-79 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में विहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में, सभी संयंत्रों से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

के—159 से के—162 से सी० टी० एफ० तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला : मेहसाना	तालुका :		कलोल
गांव	सर्वे सं०	हेक्टेयर	एआर ई	सेन्टीयर
कलोल	252/230	0	05	52
	252/230	0	10	56
	252/231	0	07	29
	252/227	0	04	32
	कार्ट ट्रेक	0	02	08
	202/215/1	0	13	12
	252/215/2	0	01	68
	252/209/2	0	02	95
	252/209/1	0	08	64
	252/207/1	0	08	88
	252/207/2	0	09	36
	कार्ट ट्रेक	0	01	76
	252/306	0	32	86
	252/310	0	10	03
	252/313	0	06	36
	252/314	0	13	42
	252/271	0	03	57
	252/270/पी	0	01	00
	252/270/पी	0	03	65
	252/370	0	08	54
	कार्ट ट्रेक	0	01	00
	252/326	0	08	00
	252/318	0	10	03
	252/325	0	15	34
	252/320	0	09	05
	266/3	0	02	81
	267	0	11	90
	268/1	0	02	81
	268/6	0	14	96
	268/5	0	01	67
	273/1	0	09	16
	273/2	0	13	82
	275	0	06	50

1	2	3	4	5
	278	0	46	38
	289	0	09	98
	कार्ट ट्रैक	0	01	75
	284	0	02	80
	285	0	08	75
	286	0	09	71
	287	0	11	00
	कार्ट ट्रैक	0	01	23
सईज	221	0	04	46
	220	0	10	50
	218	0	13	50
	216	0	10	33
	215/1	0	12	43
	214	0	29	49
	205/1	0	10	85
	205/2	0	12	72
	186	0	02	80
	204/1	0	05	43
	197	0	05	08

[सं० 12016/21/78-प्रो०]

S.O. 2219.—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. No. 258 dated 2-1-79 under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipelines;

And further in exercise of power conferred by Sub-section (4) of that Section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Oil & Natural Gas Commission free from encumbrances.

SCHEDULE

PIPELINE FROM K-159—K-162—C.T.F.

STATE : Gujarat DISTRICT : Mehsana TALUKA : Kalol

Village	Survey No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5
KALOL	252/230	0	05	52
	252/230	0	10	56
	252/231	0	07	29
	252/227	0	04	32
	Cart Track	0	02	08
	202/215/1	0	13	12
	252/215/2	0	01	68
	252/209/2	0	02	95
	252/209/1	0	08	64
	252/207/1	0	08	88
	252/207/2	0	09	36
	Cart Track	0	01	76
	252/306	0	32	86
	252/310	0	10	03
	252/313	0	06	36
	252/314	0	13	42
	252/271	0	03	57
	252/270/P	0	01	00
	252/270/P	0	03	65
	252/370	0	08	54
	Cart Track	0	01	00
	252/326	0	08	00
	252/318	0	10	03
	252/325	0	15	34
	252/320	0	09	05
	266/3	0	02	81
	267	0	11	90
	268/1	0	02	81
	268/6	0	14	96
	268/5	0	01	67
	273/1	0	09	16
	273/2	0	13	82
	275	0	06	50
	278	0	46	38
	289	0	09	98
	Cart Track	0	01	75
	284	0	02	80
	285	0	08	75
	286	0	09	71
	287	0	11	00
	Cart Track	0	01	23
Saij	221	0	04	46
	220	0	10	50
	218	0	13	50
	216	0	10	33
	215/1	0	12	43
	214	0	29	49
	205/1	0	10	85
	205/2	0	12	72
	186	0	02	80
	204/1	0	05	43
	197	0	05	08

[No. 12016/21/78-Prod.]

का० आ० 2220 —यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० एस० डी० बी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूचि मे वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एम० डी० बी० से मोटवान तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला : भरूच		तालुक : अंकलेश्वर	
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टी-यर
तेलवा	138	0	09	1
	137	0	03	90
	139	0	23	40

[सं० 12016/37/80-प्रोड० II]

S.O. 2220.—Whereas it appers to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDB to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that, any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. For Laying Flow line from well No. SDB to Motwan Header

State : Gujarat	Dist : Bharuch	Taluka : Ankleshwar		
Village	Block No.	Heat-are	Are	Cent-iare
Telva	138	0	09	10
	137	0	03	90
	139	0	23	40

[No. 12016/37/80—Prod. II]

का० आ० 2221—यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में कूप सं० एस० डी० बी० से मोटवान-1 तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाईप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए ।

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ।

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किया है ।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम अधिकारी, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग, मकरपुरा रोड, वडोदरा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा ।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत ।

अनुसूची

एम० डी० बी० से मोटवान-1 तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य—गुजरात	जिला : भरूच	तालुका	अंकलेश्वर	
गांव	ब्लॉक नं०	हेक्टेयर	ए आर ई	सेन्टी-यर
पारडी	50	0	26	00
इन्द्रीस	51	0	02	60
	49	0	20	80
	48	0	06	50
	44	0	29	00
	43	0	05	20
	33/ऐ+बी	0	02	90
	34	0	32	50
	38	0	23	40
	37	0	15	60
	110	0	03	90
	142	0	48	10
	143	0	19	60
	297	0	15	60
	298	0	06	50

[सं० 12016/37/80-प्रोड-1]

किरन चड्ढा, अवर सचिव

S.O. No. 2221—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum from SDB to Motwan-1 in Gujarat State pipelines should be laid by the Oil & Natural Gas Commission;

And whereas it appears that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interested in the said land may, within 21 days from the date of this notification object to the laying of the pipelines under the land to the Competent Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara-390 009.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heared in person or by a legal practitioner.

SCHEDULE

R.O.U. For Laying Flow line from Well No. S.D B. to Motwan Header

State : Gujarat Dist. : Bhrauch Taluka : Ankleshwar

Village	Block No.	Hect-are	Are	Cent-iare
Pardi	50	0	26	00
Indris	51	0	02	60
	49	0	20	80
	48	0	06	50
	44	0	29	00
	43	0	05	20
	33/A+B	0	02	90
	34	0	32	50
	38	0	23	40
	37	0	15	60
	110	0	03	90
	142	0	48	10
	143	0	19	60
	297	0	15	60
	298	0	06	50

[No. 12016/37/80—Prod.I]

KIRAN CHADHA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1980

का० आ० 2222—केन्द्रीय सरकार राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में कृषि मन्त्रालय (खाद्य विभाग) के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके कर्मचारी वृन्द ने हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है —

1. भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, नई दिल्ली ।
2. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, हरियाणा, चण्डीगढ ।
3. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद ।
4. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ।
5. भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला ।
6. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, इन्दौर ।
7. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, बिलासपुर ।
8. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, भोपाल ।
9. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, साबरमती ।
10. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, बड़ौदा ।
11. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, राजकोट ।
12. भारतीय खाद्य निगम, जिला कार्यालय, मुरादाबाद ।

[सं० ई० 11017/3/79-हिन्दी]

राज किशोर सिंह, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

New Delhi, the 20th August, 1980

S.O. 2222—In pursuance of sub-rule 4 of rule 10 of the Official Language (use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Ministry of Agriculture (Department of Food), the staff whereof have acquired the working knowledge of Hindi :—

1. Food Corporation of India, Zonal Office, New Delhi.
2. Food Corporation of India, Regional Office, Haryana, Chandigarh.
3. Food Corporation of India, Regional Office, Almedabad.
4. Food Corporation of India, Regional Office, Lucknow.
5. Food Corporation of India, Regional Office, Simla.
6. Food Corporation of India, District Office, Indore.
7. Food Corporation of India, District Office, Bilaspur.
8. Food Corporation of India, District Office, Bhopal.
9. Food Corporation of India, District Office, Sabarmati.
10. Food Corporation of India, District Office, Baroda.
11. Food Corporation of India, District Office, Rajkot.
12. Food Corporation of India, District Office, Moradabad.

[No. E-11017/3/79-Hindi]

R. K. Singh, Dy. Secy.

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1980

का० आ० 2223—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 9 के उप नियम (2), नियम 12 के उपनियम (2) के खंड (ख) और नियम 24 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश करते हैं कि इसमें संलग्न अनुसूची के भाग 1 और भाग 2 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" और साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" के पदों की बाबत स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, नियुक्ति प्राधिकारी होगा और स्तंभ (3) और (5) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट शास्तियों के संबंध में अनुशासन प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी होंगे ।

वन रक्षक महाविद्यालय, बालाघाट के पदों का विवरण/नियुक्ति प्राधिकारी अनुशासनिक प्राधिकारी को अधिरोपित की शास्तियों और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन अपील प्राधिकारी वर्णित करने वाली अनुसूची ।

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियों जो वह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में मद के संदर्भ सहित)		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
भाग I साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ग				
वन रक्षक महाविद्यालय, बालाघाट				
उच्च श्रेणी लिपिक और अनुसंधान सहायक श्रेणी 11 तक की श्रेणी के पद	प्रधानाचार्य वन रक्षक महाविद्यालय बालाघाट	प्रधानाचार्य वन रक्षक महाविद्यालय बालाघाट	सभी	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून
अन्य सभी पद	अध्यक्ष वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून	सभी	वन महानिरीक्षक और अपर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) देहरादून ।

1	2	3	4	5
भाग II साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह (घ)				
वन रक्षक महाविद्यालय, बालाघाट				
सभी पद	प्रधानाचार्य, वन रक्षक महाविद्यालय, बालाघाट	प्राधानाचार्य,वन रक्षक महाविद्यालय बालाघाट	सभी	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून

केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन प्राधानाचार्य, राज्यवन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर को अध्यायोजित की जाने वाली प्रस्तावित शक्तियों को दर्शित करने वाली विवरणी ।

पद का विवरण	नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी और शास्तियां जो वह अधिरोपित कर सकता है (नियम 11 में मद के संदर्भ सहित)		अपील प्राधिकारी
		प्राधिकारी	शास्तियां	
1	2	3	4	5
		भाग 1 साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर		
सभी पद	प्रधानाचार्य, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर	महाविद्यालय कोयम्बटूर प्रधानाचार्य, राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर	सभी	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून
		भाग 2 साधारण केन्द्रीय सेवा-समूह "घ" राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर		
सभी पद	प्रधानाचार्य राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर	प्रधानाचार्य राज्य वन सेवा महाविद्यालय, कोयम्बटूर	सभी	अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय देहरादून ।

[सं० 7-17/79-एफ० आर० वाई०-1]
जे० पी० भटनागार, अवर सचिव

(Deptt. of Agrl. & Coopn.)

ORDER

New Delhi, the 14th August, 1980

S.O. 2223—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 9 clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 and sub-rule (1) of rule 24 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rlues, 1965, the President hereby directs that in rerpect of the posts in the General Central Service, Group 'C' and the General Central Service, Group 'D', specified in column (1) of Part I and part II respectively of the Schedule annexed hereto, the authority specified in the column (2) shall be the appointing authority and the authorities specified in Columns (3) and (5) shall be the disciplinary authority and appellate authority respectively in regard to the penalties specified in column (4)

Schedule Showing Description of Posts, Appointing Authority, Disciplinary Authority, Penalties which may be imposed and Appellate Authority under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 Relating to Forest Rangers College, Balaghat.

Description of post	Appointing Authority	Authority competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item Number in rule (11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Part I—General Central Service, Group 'C'				
Forest Rangers College, Balaghat.				
Posts upto the grade of Upper Division Clerk and Research Assistant, Grade II'.	Principal, Forest Rangers College Balaghat.	Principal, Forest Rangers, College, Balaghat.	A..	President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.
All other posts.	President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.	President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.	All	Inspector General of Forests and ex-officio Additional Secretary to the Government of India Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture & Coopn.).
Part II—General Central Service, Group 'D'				
Forest Rangers College, Balaghat.				
All posts.	Principal, Forest Rangers College, Balaghat.	Principal Forest Rangers College, Balaghat.	All	President, Forest Research Institute and Colleges Dehra Dun.

Statement showing the Powers proposed to be delegated under the C. C. S. (C.C.A.) Rules, 1965 to the Principal, State Forest Service College, Coimbatore.

Description of post	Appointing Authority	Authority Competent to impose penalties and penalties which it may impose (with reference to item No. in Rule 11)		Appellate Authority
		Authority	Penalties.	
1	2	3	4	5
Part I—General Central Services, Group 'C'				
State Forest Service College, Coimbatore.				
All Posts	Principal, State Forest Service College, Coimbatore.	Principal, State Forest Service College, Coimbatore.	All	President Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.
Part II—General Central Service —Group 'D'				
State Forest Service College, Coimbatore.				
All Posts	Principal, State Forest Service College, Coimbatore.	Principal, State Forest Service College, Coimbatore.	All	President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun.

[No. 7-17/79—FRY—I]

J. P. BHATNAGAR, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1980

का० आ० 2224.—यतः भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उपबन्धों के अनुसरण में विश्वविद्यालय की सीनेट ने डा० टी० प्रभु, प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव विज्ञान, गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बंगलौर को पहली मई, 1980 से भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का सदस्य निर्वाचित किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्रालय की 9 जनवरी, 1960 की अधिसूचना संख्या 5-13/59-एम०-1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में 'उपधारा 3 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचित' शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 20 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर' निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"20 डा० टी० प्रभु,
प्रोफेसर, सूक्ष्मजीव विज्ञान,
गवर्नमेंट मेडिकल कालेज,
बंगलौर, कर्नाटक।"

[सं० वी० 11013/14/80-एस० ई० (पी०)]
के० वेणुगोपाल, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

S.O.2224.—Whereas in pursuance of the provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), Dr. T. Prabhu, Professor of Microbiology Government Medical College, Bangalore has been elected by the Senate of University to be a member of the Medical Council of India with effect from 1st May, 1980.

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the late Ministry of Health No. 513/59 MI dated the 9th January, 1960, namely :—

In the said notification, under the heading "Elected under clause (b) of sub-section 3", for Serial Number 20 and the entry relating thereto, the following Serial Number and entry shall be substituted, namely :—

"20. Dr. T. Prabhu,
Professor of Microbiology,
Government Medical College,
Bangalore, KARNATKA"

[No. V. 11013/14/80-M. E. (Policy)]
K. VENUGOPAL, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1980

का० आ० 2225 :—चलचित्र (सेंसर) नियमावली, 1958 के नियम 10 के साथ पठित चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, श्रीमती गौरी चटर्जी आई० ए० एस० (पश्चिम बंगाल-1971) को 26-7-80 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक श्री विवेकानंद रे के स्थान पर प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड, बम्बई, के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर स्थानापन्न रूप से काम करने के लिए नियुक्त करती है।

[फाइल संख्या 802/31/80-एफ(सी)]
के० एस० वेंकटरामन, डेस्क अधिकारी

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 18th August, 1980

S.O.2225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952), read with rule 10 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, the Central Government is pleased to appoint Smt. Gouri Chatterjee IAS (WB-1971) vice Shri Bibekananda Ray, to officiate as Regional Officer, Central Board of Film Censors, Bombay, on deputation basis with effect from 26-7-80 F.N. until further orders.

[F. 802/31/80-F(C)]
K. S. VENKATARAMAN, Desk Officer

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1980

का० आ० 2226 :—राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (2) और (4) के अनुपालन में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) मध्य रेलवे के निम्नलिखित कार्यालयों को, जहां के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करता है :—

बम्बई मंडल

1. मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय, बम्बई।
2. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर का कार्यालय, परेल।
3. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर का कार्यालय, माटुंगा।
4. उप मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर का कार्यालय, भायखला

झांसी मंडल

1. क्षेत्रीय अधीक्षक का कार्यालय, आगरा।
2. क्षेत्रीय अधीक्षक का कार्यालय, ग्वालियर।
3. क्षेत्रीय अधीक्षक का कार्यालय, भोपाल।
4. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, कानपुर।
5. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, महोबा।
6. उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कारखाना) का कार्यालय, झांसी।
7. जिला भण्डार नियंत्रक (कारखाना) का कार्यालय, झांसी।
8. कारखाना लेखा अधिकारी का कार्यालय, झांसी।
9. सिस्टम टेक्नीकल स्कूल, झांसी।

जबलपुर मंडल

1. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, कटनी।
2. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, सागर।
3. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, नरसिंहपुर।
4. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, सतना।
5. सहायक इंजीनियर का कार्यालय ब्योहारी
6. क्षेत्रीय अधीक्षक का कार्यालय, न्यू कटनी जंक्शन।
7. वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) का कार्यालय, न्यू कटनी जं०।

भुसावल मण्डल

1. सहायक विद्युत इंजीनियर (कर्षण वितरण) का कार्यालय, मनमाड।
2. सहायक इंजीनियर का कार्यालय, खंडवा।
3. सहायक इंजीनियर (अनुरक्षण) का कार्यालय, इटारसी।
4. वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (डीजल) इटारसी

5. क्षेत्रीय अधीक्षक, इटारसी ।
6. सहायक चिकित्सा अधिकारी, हरदा ।
7. सहायक चिकित्सा अधिकारी, इटारसी ।
8. सहायक चिकित्सा अधिकारी, खंडवा ।
9. सहायक इंजीनियर (पूर्व) अकोला ।
10. सहायक इंजीनियर (पश्चिम) अकोला ।
11. सहायक इंजीनियर (मीटरगेज) अकोला ।
12. सहायक इंजीनियर (ट्रेक) भुसावल ।
13. सहायक इंजीनियर (पूर्व) मनमाड ।
14. सहायक इंजीनियर (पश्चिम) मनमाड ।
15. चिकित्सा अधिकारी, भुसावल ।
16. मंडल चिकित्सा अधिकारी, इगतपुरी ।
17. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी, नांदगांव ।
18. सहायक मंडल चिकित्सा अधिकारी, मनमाड ।
19. सहायक चिकित्सा अधिकारी, पाचौरा ।
20. सहायक चिकित्सा अधिकारी, शेगांव ।
21. सहायक चिकित्सा अधिकारी, अकोला ।
22. सहायक चिकित्सा अधिकारी, वाशिम ।
23. सहायक चिकित्सा अधिकारी, मुर्तिजापुर ।
24. उप मुख्य विद्युत इंजीनियर, भुसावल ।
25. उप मुख्य इंजीनियर, मनमाड़ ।
26. क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल, भुसावल ।

सोलापुर मंडल

1. सहायक कारखाना प्रबन्धक, कुंडवाडी ।
2. सहायक चिकित्सा अधिकारी, दौंड़ ।

नागपुर मंडल

1. सहायक इंजीनियर, नैमूल ।
2. सहायक मण्डल चिकित्सा अधिकारी, आमला ।
3. सहायक इंजीनियर, बरौरा ।
4. मुख्य यार्ड मास्टर, अजनी ।
5. सहायक चिकित्सा अधिकारी, वर्धा ।
6. सहायक चिकित्सा अधिकारी, जुन्नारदेव ।
7. स्टेशन अधीक्षक का कार्यालय, नागपुर ।

[सं० हिन्दी—79/रा०मा०-15/36]

के० बालचन्द्रन, सचिव

रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, dated 14th August, 1980

S.O. 2223.—In pursuance of Sub-Rules (2) & (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for the Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Ministry of Railways (Railway Board) hereby notify the following Offices of Central Railway, the staff where of have acquired the working knowledge of Hindi:—

Bombay Division :

1. Office of the Divisional Rail Manager, Bombay.
2. Deputy Chief Mechanical Engineer, Parel.
3. Deputy Chief Mechanical Engineer, Matunga.
4. Deputy Chief S & T, Engineer, Byculla.

Jhanshi Division :

1. Office of the Area Supdt., Agra.
2. Office of the Area Supdt., Gwalior.
3. Office of the Area Supdt., Bhopal.
4. Office of the Assisant Engineer, Kanpur.
5. Office of the Assistant Engineer, Mahoba.
6. Deputy Chief Mechanical Engineer (Workshop), Jhansi.
7. District Controller of Stores (Workshop), Jhansi.
8. Workshop Accounts Officer, Jhansi.
9. System Technical School, Jhansi.

Jabalpur Division:

1. Office of the Assistant Engineer, Katni.
2. Office of the Assistant Engineer, Sagar.
3. Office of the Assistant Engineer, Narsinghpur.
4. Office of the Assistant Engineer, Satna.
5. Office of the Assistant Engineer, Beohari.
6. Office of the Area Supdt., New Kantni Junction.
7. Senior Mechanical Engineer (Diesel), New Katni Jn.

Bhusaval Division :

1. Assistant Electrical Engineer (Traction Distribution), Manmad.
2. Office of the Assistant Engineer, Khandwa.
3. Assistant Engineer (Maintenance), Itarsi.
4. Senior Divisional Mechanical Engineer (Diesel), Itarsi.
5. Office of the Area Supdt., Itarsi.
6. Assistant Medical Officer, Harda.
7. Assistant Medical Officer, Itarsi.
8. Assistant Medical Officer, Khandwa.
9. Assistant Engineer (East), Akola.
10. Assistant Engineer (West), Akola.
11. Assistant Engineer (Track), Bhusaval.
12. Assistant Engineer (Metre Gauge), Akola.
13. Assistant Engineer (East), Manmad.
14. Assistant Engineer (West), Manmad.
15. Office of the Medical Supdt., Bhusaval.
16. Divisional Medical Officer, Igatpuri.
17. Assistant Divisional Medical Officer, Manmad.
18. Assistant Divisional Medical Officer, Nandgaon.
19. Assistant Medical Officer, Pachora.
20. Assistant Medical Officer, Shegaon.
21. Assistant Medical Officer, Akola.
22. Assistant Medical Officer, Washim.
23. Assistant Medical Officer, Murtijapur.
24. Deputy Chief Electrical Engineer, Bhusaval.
25. Deputy Chief Electrical Engineer, Manmad.
26. Zonal Training School, Bhusaval.

Solapur Division :

1. Assistant Workshop Manager, Kurduvadi.
2. Assistant Medical Officer, Daund.

Nagpur Division :

1. Office of the Assistant Engineer, Betul.
2. Assistant Divisional Medical Officer, Amla.
3. Office of the Assistant Engineer, Barora.
4. Chief Yard Master, Ajni.
5. Assistant Medical Officer, Wardha.
6. Assistant Medical Officer, Junnerdeo.
7. Office of the Station Supdt., Nagpur.

[No. Hindi-79/OL-15/36]

K. BALACHANDRAN, Secretary, Railway Board & Ex. Officio Jt. Secretary

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई 1980

का० आ० 2227.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में यूनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुन्दरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास, में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटिड इंडिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास के प्रबंधतंत्र की, श्री बी० कान्नन पैकर की सेवा 11 मई, 1978 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल० 17012/4/80-डी 4 (ए)]

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 29th July, 1980

S. O. 2227.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the management of United India Insurance Co. Ltd., Madras and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section(1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sundarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of the United India Insurance Company Limited, Madras in their Regional Office at Madras in terminating the services of Shri B. Kannan, Packer, with effect from the 11th May 1978, is justified? If not, to what relief is the concerned workman entitled ?

[No. L-17012/4/80-D.IV(A)]

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1980

का० आ० 2228.—केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में यूनाइटिड इण्डिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के प्रबन्ध से सम्बद्ध एक औद्योगिक विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान है;

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 7-क और धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक औद्योगिक अधिकरण गठित करती है जिसके पीठासीन अधिकारी श्री टी० सुदरसनम डेनियल होंगे, जिनका मुख्यालय मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त औद्योगिक अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है ।

अनुसूची

क्या यूनाइटिड इण्डिया इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास के प्रबंधतंत्र की श्री पी० के० कोठानडम, पैकर की सेवा 11 मई, 1978 से समाप्त करने की कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं, तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?

[सं० एल-17012/5/80-डी 4 (ए)]

नन्द लाल, डेस्क अधिकारी।

ORDER

New Delhi, the 29th July, 1980

S. O. 2228.—Whereas the Central Government is of opinion that an industrial dispute exists between the employers in relation to the United India Insurance Company Limited, Madras and their workman in respect of the matters specified in the Schedule hereto annexed;

And, whereas the Central Government considers it desirable to refer the said dispute for adjudication;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7A, and clause (d) of sub-section (1) of section 10, of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of which Shri T. Sundarsanam Daniel shall be the Presiding Officer, with headquarters at Madras and refers the said dispute for adjudication to the said Tribunal.

SCHEDULE

Whether the action of the management of United India Insurance Company Limited, Madras in their Regional Office at Madras in terminating the services of Shri P. Kothandam, Packer, with effect from the 11th May, 1978 is justified ? If not to what relief is the concerned workman entitled?

[No. L-17012/5/80-D.IV(A)]

NAND LAL, Desk Officer

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1980

का० आ० 2229.—गजरा गोअर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टेशन रोड, देवास (मध्य प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन अनुज्ञेय हैं

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 दिसम्बर, 1979 से 30 नवम्बर, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3(क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में सदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जायेगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी ।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो यह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने के किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-35014/82/80-पी० एफ-2]

New Delhi, the 14th Aug, 1980

S. O. 2229—Whereas Messrs Gajra Gears Private Limited, Station Road, Dewas (M.P.) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central [Government hereby exempts 1st December, 1979 and up to 30th November, 1981. the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employers' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits avaliable under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 35014(82)/80-PF.II]

का० आ० 2230.—मैसर्स दि ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्युफैक्चरिंग (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड, केमिकल डिविजन, बिरलाग्राम, नागदा (मध्य प्रदेश), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधार (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 जनवरी, 1980 से उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशित भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निदिष्ट करे ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समह बीमा स्कीम के सदस्य के रुप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए जाते हैं तो, नियोजक समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है, अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जाएगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी ।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है क्योंकि छूट के लिये प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि, यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस० 35014/(73)/80-पी० एफ० II]

S. O. 2230.—Whereas Messrs Gwalior Rayon Silk Manufacturing (Wvg.) Company Limited, Chemical Division, Birla Gram Nagde, (M.P.) (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedul- annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st January, 1980 to 31st December, 1981, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enchanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh and where any amendment likely to affect adversely the interest of the emplo-

yees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving this approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely

[No. S. 35014(73)/80-PF/. II]

का० आ० 2231.—गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग भाद्रा, अहमदाबाद, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ।

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करें।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जना, बीमा प्रीमियम की संदाय, लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, गुजरात के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जायगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी ।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक वारिसों, के, जो वह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में, नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-35014/1/80-पी० एफ० (II)]

S. O. 2231.—Whereas Messrs Gujarat Steel Tubes Ltd., Bank of India, Bldg., Bhadra, Ahmedabad (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And whereas the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are without making any separate contribution or payment, of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employee than the benefits admissible under the Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Scheduled annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st January, 1980 and upto 31st December, 1981 the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall dispaly, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee that amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner, Gujarat, and where any amendment is likely to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of Indida as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 35014(1)/80-PF-II]

का० आ० 2232.—मीरा एण्ड कम्पनी, जी० टी० रोड, लुधियाना, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 17 की उपधारा (2क) के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्मचारी, कोई पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही, भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के रूप में फायदा उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप से सम्बद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को, 1 मार्च, 1979 से 28 फरवरी, 1981 तक उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है ।

अनुसूची

1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब को ऐसी विवरणियां भेजेगा, ऐसे लेखा रखेगा और निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर निर्दिष्ट करे ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति से 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3क) के खण्ड (क) के अधीन निर्दिष्ट करें ।

3. समूह बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का परीक्षण, निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा ।

4 नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित समूह बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए तब उस संशोधन की एक प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले से सदस्य है, उक्त स्थापन में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाये जाते हैं तो, नियोजक, समूह बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए समूह बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. समूह बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदाय रकम उस रकम से कम है जो उस कर्मचारी की दशा में देय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नामनिर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अंतर के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

8. समूह बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, पंजाब के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9 यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम की उस समूह बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है अधीन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रद्द कर दी जायेगी ।

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो, छूट रद्द कर दी जाएगी ।

11. यदि नियोजक, प्रीमियम के संदाय, आदि में कोई व्यतिक्रम करता है तो, उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों के, जो वह छूट न दी जाने की दशा में उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा फायदों के संदाय का, उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, उसके हकदार नामनिर्देशितियों/विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देनी आवश्यक हो गई है, क्योंकि छूट के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की कार्रवाई पर समय लगा । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-35014/83/80-पी०एफ० 2]

S.O. 2232.—Whereas Messrs Meera and Company, G. T. Road, Ludhiana, (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act);

And Whereas, the Central Government is satisfied that the employees of the said establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in the Schedule annexed hereto, the Central Government hereby exempts with effect from 1st March, 1979 and upto 28th February, 1981, the said establishment from the operation of all the provisions of the said Scheme.

THE SCHEDULE

1. The employer in relation to the said establishment shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner, Punjab, maintain such accounts and provide for such facilities for inspection, as the Central Government may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges, etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display, on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government and, as and when amended, alongwith a translation of the salient features thereof, in the language of the majority of the employees.

5. Where an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment, the employer shall immediately enrol him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of *India*.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately, if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced, so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amount payable under this Scheme be less than the amount that would be payable had employee been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the legal heir/nominee of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner Punjab and where any amendment is likeby to affect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where, for any reason, the employees of the establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where, for any reason, the employer fails to Pay the premium within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption is liable to be cancelled.

11. In case of default, if any, made by the employer in payment of premium etc., the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee or legal heirs of deceased members who would have been covered under the said Scheme but for grant this exemption, will be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Scheme the employer in relation to the said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee/legal heirs entitled for it and in any case within 7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insurance Corporation of India.

Explanatory Memorandum

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the processing of the application for exemption took time. However, it is certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S. 35014 (83)/80-PF.II]

का० आ० 2233.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डा० एम० जी०, पॉल, बैक्टेरियोलॉजिकल लेबोरेटरीज, 131 सी, विधान सरणी, कलकत्ता-4, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 15 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35017/(1)/80-पी० एफ-II]

S.O. 2233.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Dr. M.C. Paul's Bacteriological Laboratories, 131 C, Bidhan Sarani, Calcutta-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1962), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the fifteenth day of April, 1979.

[No. S. 35017(1)/80-PF. II]

का० आ० 2234.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स खातून महल, क्यू 47, एकरा रोड, मेंतियाबुज, कलकत्ता-74, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1974 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(63)/79-पी० एफ०-II]

S.O. 2234.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Khatoon Mahal, Q 47, Akra Road, Metiabruz, Calcutta-74, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1974.

[No. S. 35017(63)/79-PF. II]

का० आ० 2235.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स पेपर एण्ड प्लास्टिक प्रोडक्टस् 14/1/1ए, जैक्सन गली, कलकत्ता-1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अगस्त, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(64)/79- पी० एफ०-II]

S.O. 2235.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Paper and Plastic Products, 14/1/1A, Jackson Lane, Calcutta-1, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment :

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of August, 1978.

[No. S-35017(64)79-PF. II]

का० आ० 2236.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ए० एस० पी० इम्पलाईज कोआपेरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, एलाय स्टील, प्लांटस, दुर्गापुर-713208, पश्चिमी बंगाल, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 2 मई, 1978 को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(67)/79 पी० एफ० II]

S.O. 2236.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs A.S.P. Employees' Co-operative Credit Society Limited, Administrative Buildings, Alloy Steel Plants, Durgapur-713208 West Bengal, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers, conferred by-sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government herely applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the second day of May 1978.

[No. S-35017(67)/79-P.F. II]

का० आ० 2237.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जे० पी० इंजीनियरिंग वर्क्स, 17-ए, इण्डियन मीरर स्ट्रीट, कलकत्ता 13, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(71)/79 पी० एफ० II]

S.O. 2237.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Jaypee Engineering Works, 17-A, Indian Mirror Street, Calcutta-13, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1978.

[No. S-35017(71)/79-P.F. II]

का० आ० 2238.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, मैसर्स रूबी टी० एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज (प्राइवेट) लिमिटेड, 235/2, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता-20, जिसके अन्तर्गत (1) अनिलकुमार टी० वेयर हाउस, बज बज ट्रंक रोड, 24-परगना (पश्चिमी बंगाल) और (2) डाक घर इक्तियासल सेवोक रोड, सिलीगुड़ी, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(72)/79- पी० एफ०II]

S.O. 2238.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Ruby Tea and Allied Industries (Private) Limited, 235/2, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Calcutta-20, including its branches at (1) Anilnagar Tea Warehouse, Budge Budge Trunk Road 24-Parganas (West Bengal) and (2) Post Office Ektiasal Sevoke Road, Siliguri, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made, applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1978.

[No. S. 35017(72)/79-P.F. II]

का० आ० 2239.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोमाशन सर्विसेज, 41/1, मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-16 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस० 35017(82)/79-पी० एफ०-II]

S.O. 2239.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kosaban Services, 41/1, Mirza Galib Street, Calcutta-16, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of December, 1978.

[No. S. 35017(82)/79—P.F. II]

का०आ० 2240.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स हिन्द ट्रेडिंग कम्पनी, 143 कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता-7 जिसके अन्तर्गत ए०टी० रोड, गोहाटी, असम, स्थित उसकी शाखा भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 जुलाई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं०एस०-35017(83)/79-पी०एफ-2(i)]

S.O. 2240.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the Majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Hind Trading Company, 143, Cotton Street, Calcutta-7 including its branch at A.T. Road, Gauhati, Assam, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty first day of July, 1978.

[No. S-35017/83/79—P.F. II(i)]

का०आ० 2241.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 जुलाई, 1978 से मैसर्स हिन्द ट्रेडिंग कम्पनी, 143, कॉटन स्ट्रीट, कलकत्ता-7, जिसके अन्तर्गत ए०टी०, रोड, गोहाटी, असम, स्थित उसकी शाखाएं भी है।

नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा०सं० एस० 35017/(83)79-पी०एफ०-II(ii)]

S.O. 2241.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of July, 1978 the establishment known as Messrs Hind Trading Company, 143, Cotton Street, Calcutta 7 including its branch at A.T. Road, Gauhati, Assam, for the purposes of the said proviso.

[No. S. 35017(83)/79-PF. II(ii)]

का०आ० 2242.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स आटो सुपर सर्विस, 65, अरविन्द सारणी, कलकत्ता-5, जिसके अन्तर्गत 9/1/1 ए, सुराह प्रथम गली, कलकत्ता-10, स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं –

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017(85)/79-पी०एफ-2 (i)]

S.O. 2242.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Auto Super Service, 65, Aravind Sarani, Calcutta-5, inlcuding its branch at 9/1/1A, Surah First Lane, Calcutta-10, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notication shall be deemed to have come into force on the thirty first day of March, 1979.

[No. S. 35017(85)/79-PF. II(i)]

का०आ० 2243.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात 31 मार्च, 1979 से मैसर्स आटो सुपर सर्विस, 65, अरविन्द सारणी, कलकत्ता-5, जिसके अन्तर्गत 9/1/1 ए, सुराह प्रथम गली, कलकत्ता-10, स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा०स० 35017/85/79-पी-एफ-2(ii)]

S.O. 2243.—In exercise of the powers conferred y the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act

1952 (19 of 1952) , the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty first day of March, 1979 the establishment known as Messrs Auto Super Service, 65, Aravind Sarani, Calcutta-5 including its branch at 9/1/1A, Surah First Lane, Calcutta-10 for the purposes of the said proviso.

[No.S.35017/85/79-PF.II(ii)]

का०आ० 2244—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स ह्मबोल्डेट वेडाग इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड, 50, चौरंगी रोड, कलकत्ता-71, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35017/86/79 पी०एफ०-II]

S. O. 2244.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Humboldt Wedag India (Private) Limited, 50, Chowringhee Road, Calcutta-71 have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March 1979.

[No.S-35017/86/79-PF.II]

का०आ० 2245.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल 1979 से मैसर्स डाटा इंजीनियरिंग कम्पनी, 28 टाउन सेंड रोड, कलकत्ता-25 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा०सं० एस०35017(92)/79-पी०एफ०-II(ii)]

S.O. 2245.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1979 the establishment known as Messrs Data Engineering Company, 28, Town Send Road, Calcutta-25, for the purposes of the said proviso.

[No.S.35017(92)/79-PF.II(ii)]

का०आ० 2246.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बोम्बे आटो रिपावरिंग जे० फारिया इंडस्ट्रियल इस्टेट, 35/43, मुसा लिदार स्ट्रीट, कलर्क रोड, जैकोब सर्किल, मुम्बई-11 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(2)/80-पी०एफ०-II]

S. O. 2246.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bombay Auto Repowering, J. Karia Industrial Estate, 35/43, Musa Killedar Street, Clerk Road, Jacob Circle, Bombay-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April 1979.

[No.S.35018(2)/80-PF.II]

का०आ० 2247.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स बोम्बे बोरिंग वर्क्स, 1, कारिया इण्डस्ट्रियल इस्टेट, यूनिट नं 48 से 52 तक, 35/43, मुसा किलेदार स्ट्रीट, कलर्क रोड, जैकोब सर्किल, मुम्बई-11 जिसके अन्तर्गत 8, प्रसाद चैम्बर्स, मुम्बई-4 स्थित उसकी शाखा भी है, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रदत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018(4)/80-पी०एफ-II]

S.O. 2247.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Bombay Boring Works, 1, Karia Industrial Estate, Unit No.48 to 52, 35/43, Musa Killedar Street,

Clerk Road, Jacob Circle, Bombay-11 including its Office at 8, Prasad Chambers, Bombay-4, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No.S. 35018(4)/80-PF.II]

का० आ० 2248.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मेकवेल इण्डस्ट्रीज, राज बकेट फैक्टरी कम्पाउंड, घोड़ बंदर रोड़, जिला थाना पश्चिमी रेलवे, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 अक्तूबर, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018 (5)/80-पी० एफ०-II(1)]

S.O. 2248.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Mech-Well Industries, Raj Bucket Factory Compound, Ghod Bunder Road, District Thana, Western Railway, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of October, 1978.

[S. No. 35018(5)/80-P.II (i)]

का० आ० 2249.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स क्लीनवेल (इण्डिया), पहली मंजिल, जनरल एश्यूरेंस बिल्डिंग, 232, डी० एन० रोड़, मुम्बई-1, जिसके अन्तर्गत (1) बंगलौर डाकघर 2705, बंगलोर-27, (2) कोचीन डाकघर 1790, कोचीन-16 और (3) इंदौर, देवास, इंदौर (मध्य प्रदेश), स्थित उसकी शाखाएं भी है, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(9)/80-पी० एफ-II]

S.O. 2249.—Whereas it appears to the ntral Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Kleenwel (India), 1st Floor, General Assurance Building, 232, D.N. Road, Bombay-1 including its branches at (1) Bangalore Post Box 2705, Bangalore-27, (2) Cochin Post Box 1790, Cochin-16 and (3) Indore, Devas, Indore (Madhya Pradesh) have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of March 1979.

[No.S.35018(9)/80-PF.II]

का० आ० 2250.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वी० के० पम्प इण्डस्ट्रीज, 39-बी, सुरेन रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-93, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 30 जून, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(23)/79-पी० एफ-II]

S.O. 2250.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs V.K. Pump Industries, 39-B, Suren Road Andheri (East) Bombay-93, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hrereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of June, 1978.

[No. 35018(23)/79-PF. II]

का०आ० 2251.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स लेक्ट्रोटेक, 33, पार्वती इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पूणे-9, नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापना को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 31 मई, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35018(111)/79-पी० एफ-II]

S.O. 2251.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Lectrotek, 33, Parvati Industrial Estate, Pune-9, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of May, 1978.

[No. S.35018(111)/79-PF.II]

का०आ० 2252.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1978 से मैसर्स कोवेंटरी स्प्रिंग एंड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, डी-2, एम० आई० डी० सी० इण्डस्ट्रियल एरिया, नागपुर-16, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस-35018/115/79-पी० एफ०-II (ii)]

S.O. 2252.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1978 the establishment known as Messrs Coventry Spring and Engineering Company (Private) Limited, D-2, MIDC Industrial Area, Nagpur-16. for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(115)/79-PF. II(ii)]

का०आ० 2253.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डी० एस० पी० फाइनांसियल, कंसल्टेंटस लिमिटेड, 4, स्टोक एक्सचेंज बिल्डिंग, पहला फ्लोर, एपोलो स्ट्रीट, मुम्बई-23 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस-35018 (129)/79 पी० एफ०-II]

S.O. 2253.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs D. S. P. Financial Consultants Limited, 4, Stock Exchange Building, 1st Floor, Apollo, Street, Bombay-23, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieth day of April, 1978.

[No. S-35018(129)/79-PF.II]

का०आ० 2254.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स वायर रोलिंग इण्डस्ट्रीज, ए-66, पहला फ्लोर, विरवानी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, वैस्टर्न एक्सप्रैस हाइवे, गोरेगांव (पूर्व), मुम्बई-63, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 31 मार्च, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018 (131)/79-पी० एफ०-II]

S.O. 2254.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs Wire Rolling Industries, A-66, 1st Floor, Virwani Industrial Estate, Western Express Highway, Goregaon (East), Bombay-63, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirty-first day of March, 1979.

[No. S-35018(131)/79-PF.II]

का०आ० 2255.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एक्यूट्रोल सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड, 15वां फ्लोर, निर्मल, नरीमन प्वाइंट मुम्बई-21, जिसके अन्तर्गत 11वां फ्लोर, एक्सप्रैस टावर्स, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-21, स्थित उसका विक्रय कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 जनवरी, 1979 को प्रवृत्त समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018 (133)/79-पी० एफ०-II (1)]

S.O. 2255.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in

relation to the establishment known as Messrs Accutrol System (Private) Limited, 15th Floor, Nirmal, Nariman Point, Bombay-21 including its Sales Office at 11th Floor, Express Towers, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of January, 1979.

[No. S-35018(133)/79-PF. II(i)]

का०आ० 2256.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1979 से मैसर्स एक्यूट्रोल सिस्टम (प्राइवेट) लिमिटेड 15वां फ्लोर निर्मल, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-21, जिसके अन्तर्गत 11वां फ्लोर, एक्सप्रैस टावर्स नरीमन प्वाइंट, मुम्बई-21 स्थित उसका विक्रय कार्यालय भी है, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० एस०-35018 (133)/79-पी० एफ० II (2)]

S.O. 2256.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1979, the establishment known as Messrs Accutrol System (Private) Limited, 15th Floor, Nirmal, Nariman Point, Bombay-21, including its Sales Office at 11th Floor, Express Towers, Nariman Point, Bombay-21, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(133)/79-PF.II(ii)]

का०आ० 2257.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संम्बद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जनवरी, 1979 से मैसर्स एल्युमिनेक्स (इण्डिया) (प्राइवेट) लिमिटेड 6वां फ्लोर, रेमन हाउस, 169, बैकबे, रिक्लेमेशन, मुम्बई-20 नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० एस०-35018 (135)/79-पी० एफ०-II (2)]

S.O. 2257.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of January, 1979 the establishment known as Messrs Aluminex (India) (Private) Limited, 6th Floor, Ramon House, 169, Backbay, Reclamation, Bombay-20, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(135)/79-PF.II(ii)]

का०आ० 2258.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स डाटाकौम कम्प्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, पहला फ्लोर, 1-2 रिजेण्ट चैम्बर्स, 208, नरीमन प्वांइट, मुम्बई-21, नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018 (142)/79 पी० एफ० II(i)]

S.O. 2258.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Datacom Computor Service (Private) Limited, 1st Floor, 1-2 Regent Chambers, 208, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No. S-35018(142)/79-PF.II(i)]

का०आ० 2259.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1979 से मैसर्स डाटाकोम कम्प्यूटर सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड, पहला फ्लोर, 1-2 रिजेण्ट चैम्बर्स, 208, नरीमन प्वाइंट मुम्बई-21, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० एस०-35018 (142)/79-पी० एफ० II(2)]

S.O. 2259.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1979 the establishment known as Messrs. Datacom Computer Services (Private) Limited, 1st Floor, 1-2 Regent Chambers, 208, Nariman Point, Bombay-21, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(142)/79-PF.II(ii)]

का०आ० 2260.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स जनरल सेल्स एजेंसीज, 57, कृष्णा भवन, लोहार चाल, मुम्बई-2, नामक स्थापन से संबंद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है।

यह अधिसूचना 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

[सं० एस०-35018(145)/79 पी० एफ० II]

S.O. 2260.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. General Sales Agencies, 57, Krishna Bhavan, Lohar Chawl, Bombay-2, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the thirtieh day of April, 1979.

[No. S-35018(145)/79-PF. II]

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 1980

का० आ० 2261.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 31 अक्तूबर, 78 से मैसर्स मेक वेल इण्डस्ट्रीज, राज बकेट फैक्टरी कम्पाउंड, घोड बंदर रोड, जिला थाना, पश्चिमी रेलवे, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनो के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[फा० सं० एस० 35018(5)/80-पी० एफ० 2(ii)]

New Delhi, the 19th August, 1980

S.O. 2261.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the thirty-first day of October, 1978, the establishment known as Messrs. Mech. Well Industries, Raj Bucket Facorty Compound, Ghod Bunder Road, District Thana, Western Railway, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35018(5)/80-PF.II(ii)]

का० आ० 2262.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स कोकरैन बॉयलर कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, 229, टोडी इण्डस्ट्रियल इस्टेट, 316 एन० एम० जोशी मार्ग, डिलाइस्ले रोड, मुम्बई-11, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 मई, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस० 35018(122)/79-पी० एफ० 2]

S.O. 2262.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Kokran Boiler Company (Private) Limited, 229, Todi Industrial Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Delisle Road, Bombay-11, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of May, 1979.

[No. S-35018(122)/79-PF.II]

का० आ० 2263.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स एल्मीन इण्डस्ट्रीज, नं० 4, स्मिथ रोड, मद्रास-2, जिसके अन्तर्गत (1) 4 वाइट्स रोड, मद्रास-14 और (2) कर्मशाला, नं० 84-डी, लैटिस ब्रिज रोड, मद्रास-41 स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 जून, 1978 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस-35019(268)/79-पी० एफ०-2(1)]

S.O. 2263.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Almin Industries, No. 4, Smith Road, Madras-2 including its branches at (1) 4, Whites Road, Madras-14, and (2) Workshop at No. 84-D, Lattice Bridge Road, Madras-41, have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies to the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of June, 1978.

[No. S-35019(268)/79-PF. (II)(i)]

का० आ० 2264.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 जून, 1978 से मैसर्स एल्मीन इण्डस्ट्रीज, नं० 4, स्मिथ रोड, मद्रास-2, जिसके अन्तर्गत (1) 4 वाइट्स रोड, मद्रास-14 और (2) कर्मशाला, 84 डी, लैटिस ब्रिज रोड, मद्रास-41, स्थित उसकी शाखाएं भी हैं, नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019(268)/79-पी० एफ०-2(II)]

S.O. 2264.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of June, 1978, the establishment known as Messrs. Almin Industries, No. 4, Smith Road, Madras-2, including its branches at (1) 4, Whites Road, Madras-14 and (2) Workshop at 84-D, Lattice Bridge Road, Madras-41, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(268)/79-PF.II(ii)]

का० आ० 2265.—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि मैसर्स मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मालविया नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952(1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है ।

यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

[सं० एस०-35019(272)/79-पी० एफ०-2 (1)]

S.O. 2265.—Whereas it appears to the Central Government that the employer and the majority of the employees in relation to the establishment known as Messrs. Madhya Pradesh Export Corporation Limited, Malvia Nagar, Bhopal (Madhya Pradesh), have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions

Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the said establishment ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 1 of the said Act, the Central Government hereby applies the provisions of the said Act to the said establishment.

This notification shall be deemed to have come into force on the first day of April, 1979.

[No. S-35019(272)/79-PF.II(i)]

का० आ० 2266.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध विषय में आवश्यक जांच करने के पश्चात् 1 अप्रैल, 1979 से मैसर्स मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, मालविया नगर, भोपाल (मध्य प्रदेश) नामक स्थापन को उक्त परन्तुक के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट करती है।

[सं० एस०-35019/272/79-पी० एफ०-2(ii)]

S.O. 2266.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies with effect from the first day of April, 1979, the establishment known as Messrs. Madhya Pradesh Export Corporation Limited, Malvia Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh, for the purposes of the said proviso.

[No. S-35019(272)/79-PF.II(ii)]

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 1980

का० आ० 2267.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 91क के साथ पठित धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1000, दिनांक 28 फरवरी, 1979 के अनुक्रम में, भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था, जयपुर की इंजीनियरिंग प्रभाग के नियमित कर्मचारियों को पहली जनवरी, 1979 से 31 दिसम्बर, 1979 तक उक्त अधिनियम के प्रवर्तन से एक वर्ष की अवधि के लिए छूट देती है ।

2. पूर्वोक्त छूट की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात् :—

(1) पूर्वोक्त कारखाना, जिसमें कर्मचारी नियोजित हैं, एक रजिस्टर रखेगा, जिसमें छूट प्राप्त कर्मचारियों के नाम और पदाभिधान दिखाये जाएंगे;

(2) इस छूट के होते हुए भी, कर्मचारी उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करते रहेंगे, जिनको पाने के लिए वे इस अधिसूचना द्वारा दी गई छूट के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व संदत्त अभिदायों के आधार पर हकदार हो जाते;

(3) छूट प्राप्त अवधि के लिए यदि कोई अभिदाय पहले ही किए जा चुके हों तो वे वापिस नहीं किये जाएंगे;

(4) उक्त कारखाने का नियोजक उस अवधि की बाबत जिसके दौरान उस कारखाने पर उक्त अधिनियम प्रवर्तमान था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अवधि" कहा गया है), ऐसी विवरणियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों सहित देगा जो कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के अधीन उसे उक्त अवधि की बाबत देनी थीं;

(5) निगम द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त किया गया कोई निरीक्षक, या निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य पदधारी :—

(i) धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त अवधि की बाबत दी गई किसी विवरणी की विशिष्टियों को सत्यापित करने के प्रयोजनार्थ; या

(ii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्टर और अभिलेख उक्त अवधि के लिए रखे गए थे या नहीं; या

(iii) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि कर्मचारी, नियोजक द्वारा दिए गए उन फायदों को, जिसके प्रतिफल स्वरूप इस अधिसूचना के अधीन छूट दी जा रही है, नकद में और वस्तु रूप में पाने का हकदार बना हुआ है या नहीं; या

(iv) यह अभिनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि उस अवधि के दौरान, जब उक्त कारखाने के संबंध में अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त थे, ऐसे किन्हीं उपबंधों का अनुपालन किया गया था या नहीं ।

निम्नलिखित कार्य करने के लिए सशक्त होगा :—

(क) प्रधान या अव्यवहित नियोजक से अपेक्षा करना कि वह उसे ऐसी जानकारी दे जिसे उपरोक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी आवश्यक समझता है;

(ख) ऐसे प्रधान या अव्यवहित नियोजक के अधिभोगाधीन किसी कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में किसी भी उचित समय पर प्रवेश करना और उसके प्रभारी से यह अपेक्षा करना कि वह व्यक्तियों के नियोजन और मजदूरी के संदाय से संबंधित ऐसे लेखा, बाहियां और अन्य दस्तावेज ऐसे निरीक्षक या अन्य पदधारी के समक्ष प्रस्तुत करे और उनकी परीक्षा करने दे, या उन्हें ऐसी जानकारी दे जिसे वे आवश्यक समझते हैं; या

(ग) प्रधान या अव्यवहित नियोजक की, उसके अभिकर्ता या सेवक की, या ऐसे किसी व्यक्ति की जो ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में पाया जाए, या ऐसे किसी व्यक्ति की जिसके बारे में उक्त निरीक्षक या अन्य पदधारी के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि वह कर्मचारी है, परीक्षा करना या

(घ) ऐसे कारखाने, स्थापन, कार्यालय या अन्य परिसर में रखे गए किसी रजिस्टर, लेखाबही या अन्य दस्तावेज की नकल तैयार करना या उससे उद्धरण लेना ।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

इस मामले में छूट को पूर्वापेक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है, क्योंकि छूट की मंजूरी के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सिफारिश देर से प्राप्त हुई । तथापि यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्वापेक्षी प्रभाव से छूट देने से किसी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

[संख्या एस-38014/4/79-एच० आई०]

हंसराज छाबड़ा, उप सचिव

New Delhi, the 20th August, 1980

S.O. 2267.—In exercise of the powers conferred by section 88 read with section 91A of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 1000 dated the 28th February, 1979, the Central Government hereby exempts the regular employees of the Engineering Division of the Geological Survey of India, Jaipur from the operation of the said Act for a period of one year with effect from the 1st day of January, 1979 upto and inclusive of the 31st day of December, 1979.

The above exemption is subject to the following conditions, namely :—

(1) The aforesaid factory wherein the employees are employed shall maintain a register showing the names and designations of the exempted employees;

(2) Notwithstanding this exemption, the employees shall continue to receive such benefits under the said Act to which they might have become entitled to on the basis of the contributions paid prior to the date from which exemption granted by this notification operates;

(3) The contributions for the exempted period, if already paid, shall not be refunded ;

(4) The employer of the said factory shall submit in respect of the period during which that factory was subject to the operation of the said Act (hereinafter referred to as the said period), such returns in such form and containing such particulars as were due from it in respect of the said period under the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950;

(5) Any Inspector appointed by the Corporation under sub-section (1) of section 45 of the said Act, or other Official of the Corporation authorised in this behalf shall, for the purposes of—

(i) verifying the particulars contained in any return submitted under sub-section (1) of section 44 for the said period; or

(ii) ascertaining whether registers and records were maintained as required by the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950 for the said period; or

(iii) Ascertaining whether the employees continue to be entitled to benefits provided by the employer in cash and kind being benefits in consideration of which exemption is being granted under this notification; or

(iv) ascertaining whether any of the provisions of the Act had been complied with during the period when such provisions were in force in relation to the said factory

be empowered to—

(a) require the principal or immediate employer to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(b) enter any factory, establishment, office or other premises occupied by such principal or immediate employer at any reasonable time and require any person found incharge thereof to produce to such Inspector or other official and allow him to examine such accounts, books and other documents relating to the employment of persons and payment of wages or to furnish to him such information as he may consider necessary; or

(c) examine the principal or immediate employer, his agent or servant, or any person found in such factory, establishment, office or other premises, or any person whom the said Inspector or other official has reasonable cause to believe to have been an employee; or

(d) make copies of or take extracts from, any register, account book or other document maintained in such factory, establishment, office or other premises

EXPLANATORY MEMORANDUM

It has become necessary to give retrospective effect to the exemption in this case, as the recommendation of the Employees' State Insurance Corporation for grant of exemption was received late. It is, however, certified that the grant of exemption with retrospective effect will not affect the interest of anybody adversely.

[No. S.38014/4/79-HI]

HANS RAJ CHHABRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 19th August, 1980

S O. 2268.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Jogidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad and their workmen, which was received by he Central Government on the 12th August, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Sec. 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947

Reference No. 45 of 1977

PARTIES :

Employers in relation to the management of Jogidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad.

AND

Their Workmen.

PRESENT :

Mr. Justice B. K. Ray, Presiding Officer.

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate.

For the Workmen—Shri S. Bose, Secretary Colliery Mazdoor Sangh, Dhanbad.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dhanbad, dated, the 1st August, 1980

AWARD

By Order No. L-20012/42/75/D. III. A and L. 20012/36/75/D. III. A, dated, the 4th September, 1975, the Central Government in exercise of their powers under clause (d) of sub-sec. (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, have referred for adjudication the dispute as given in the schedule to the order. The schedule to the order reads thus :

"Whether the action of the management of Jogidih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Tundoo, District Dhanbad, in dismissing from service Sarva Shri B. N. Sinha, Cashier and P. C. P. Lala, Bill Clerk with effect from the 26th June, 1974, is justified? If not to what relief are the said workmen entitled?"

2. After notice to the parties they have filed their respective written statements. The workmen concerned have filed a rejoinder denying the allegations made in the written statement of the management. As the workmen in their written statement challenged the fairness of the domestic enquiry in which they were found guilty as a result of which they

were dismissed from service and as the management in its written pleaded that the domestic enquiry was fair and proper in all respects, at the instance of parties the question regarding fairness of the domestic enquiry was taken up prior to hearing of the case on merit and by Order dated 30-11-1978 my predecessor has held that the domestic enquiry is fair and proper. At the time of hearing on preliminary point regarding fairness of the domestic enquiry a point was taken by the union on behalf of the concerned workmen that the order of dismissal issued against them by the manager of the colliery in question was invalid in asmuchas the manager was not competent to pass an order of dismissal of the workmen as per the provisions of the Standing Orders applicable to the colliery. While dealing with the point my predecessor in paragraph 3 of his order has held that the manager of the colliery was the proper authority to pass an order of dismissal against the workmen. The paragraph dealing with the point reads thus :

> "When there was no specific Standing Orders framed by the erstwhile owner, it will be deemed under Sec. 12A of Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946, that Model Standing Orders applied to the establishment. Schedule 1A of the Act lays down the provisions of Model Standing Orders. Clause 2(b) of the said orders adopts the definition of employer' as given in Clause d(iii) of Section 2 of the Act, which says that employer shall include 'any person responsible to the owner for the supervision and control of the industrial establishment. Manager is such a person. As such Manager is included within the definition of the word 'employer' used in Clause 13 of the Model Standing Orders which says, that employer (Manager) was competent to terminate the services of an employee. In this way the termination of the employment by the Manager was not without jurisdiction nor can it be said to be void on that account. The last mentioned objection has thus no force."

From the above paragraph it appears that there is no certified Standing Orders in colliery in question and it is governed by Model Standing Orders as given in Schedule 1A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946. At the time of hearing of the case on merit it is contended on behalf of the workmen that Model Standing Orders as observed by my predecessor has no application to the colliery in question and the Model Standing Orders for coal mining industry which is something different from the Model Standing Orders as given in Schedule 1A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 applies to the colliery in question. So the finding of my predecessor that the manager is the competent authority to pass an order of dismissal arrived at on the basis that the Model Standing Orders as given in Schedule 1A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 is applicable must be held to be wrong. But by comparing the Model Standing Orders as given in Schedule 1A(c) of the Industrial Employment (Standing Orders) Act with the Model Standing Orders for Coal Mining Industry a copy of which has been supplied by Mr. S. Bose it is found that substantially the Standing Orders in both are same. Paragraph 17 of the Model Standing Orders for Coal Mining Industry relied upon by Mr. Bose which paragraph deals with disciplinary action against a workman in a coal mining industry and deals with the provision for dismissing him is almost identical with the corresponding provision in the Model Standing Orders under the Act. That being so it must be held that my predecessor by his order dated 30-11-1978 has decided the point against the union. So for the purpose of this case it must be held that the manager has authority to dismiss a workman in the colliery in question. Mr. Bose now argues that at the time when the question regarding the preliminary point about fairness of the domestic enquiry was decided my predecessor should not have dealt with the point regarding the authority of the manager to dismiss a workman in a coal mining industry. Therefore the decision of my predecessor on the point should not be held to be final and conclusive for this case. I am afraid this contention of Mr. Bose cannot be accepted. A reading of the order dated 30-11-1978 shows that the point relating to the authority of the manager to dismiss a workman was taken at the time when the preliminary point regarding fairness of the domestic enquiry was taken. Parties at that time advanced their respective arguments on the point and my predecessor therefore was fully justified in giving his decision on the point. That apart if what Mr. Bose now says is correct immediately after the order dated 30-11-1978 was brought to his notice he should have filed an application before the Tribunal saying that it should not have decided the question regarding the authority of the manager to dismiss a workman while deciding the preliminary point regarding fairness of the domestic enquiry as the point was not urged at the time the case was heard on preliminary point regarding fairness of domestic enquiry. Not having done so and having kept silent from 1978 till today it is not open to Mr. Bose now to say that my predecessor was not aksed to deal with the question regarding authority of the manager to dismiss a workman at the time he was deciding the question regarding the fairness of the domestic enquiry. Therefore in my view for all purposes it must be held so far as this case is concerned that the point regarding the authority of the manager to dismiss a workman has been decided by order dated 30-11-78 finally and it is not open now to re-agitate the same point once again at the time of final hearing of the case. Even inspite of this at the time of hearing of the case on merit management wanted to abduce evidence to show that the order of dismissal of the workmen concerned issued by the manager had the approval of the General Manager of the colliery who was the Chief Mining Engineer. On this particular point management examined MW-2 who deposes that the order of dismissal issued by the manager against the concerned workmen had the approval of the General Manager who was the Chief Mining Engineer. This evidence of the witness has been challenged unsuccessfully in cross-examination by Mr. Bose. But the witness has undertaken to produce documents within a time to be fixed by the Court to show that the General Manager was acting as Chief Mining Engineer at the time when he approved the dismissal order against the workmen. I had to wait for ten days to enable the witness to produce the documents before passing the award. Ten days have elapsed and no document has been produced as undertaken by MW-2. But in view of my conclusion reached above it is not possible to say now that the manager had no authority to issue order of dismissal against the concerned workmen because he was neither the owner nor the agent nor the Chief Mining Engineer. That being the position even non-production of document by MW-2 to show that the General Manager at the relevant time was acting as Chief Mining Engineer will not be fetal to the case so far as the management is concerned.

3. There are two workmen in the case who have been dismissed and it is these orders of dismissal which are in challenge in the case. I shall deal with the case of each workmen separately.

4. I first take up the case of the workman Shri B. N. Sinha who is said to be working as Cashier at the time he was dismissed from service. The chargesheet Ext. M-1 shows that he was charged for making double payment to S/Shri (1) Balaram Bouri, (2) Joga Bouri, (3) Gour Bouri, (4) Binod Bouri and (5) Panwa Bhuiya in respect of their wages for the week ending on 11-2-1974. In paragraph 2 of the charge it has been said that S/Shri Balaram Bouri, Joga Bouri and Gour Bouri have stated that they received only single payment while Shri Panwa Bhuiya has admitted to have received double payment. It is also stated in the same paragraph that Shri Binod Bouri did not appear at the preliminary enquiry. After saying so it has been stated in that paragraph in the chargesheet that payment in respect of S/Shri Joga Bouri, Gouri Bouri and Balaram Bouri have been misappropriated by the delinquent. On these allegations Sri B. N. Sinha has been chargesheeted with dishonesty in connection with company's business which is a misconduct under the Standing Orders. It is admitted that there is no certified Standing Orders so far as the colliery in question is concerned. Therefore, the provisions of the Model Standing Orders as mentioned in Schedule 1A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 would apply. But as has been indicated above according to Mr. Bose for the workman it is not the Model Standing Orders as given in Schedule 1A of the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 which would apply. According to Mr. Bose the Model Standing Orders for coal mining industry separately

published would apply. Even accepting Mr. Bose's contention to be correct I have already observed that provisions regarding disciplinary action for misconduct as given in both the Standing Orders are almost the same. Under these Standing Orders theft, fraud or dishonesty in connection with the employer's business or property is a misconduct which entails the punishment of dismissal. True in the chargesheet against Sri Sinha it has not been stated under which paragraph of the Standing Orders his alleged act of misconduct comes. But it has been clearly stated in the chargesheet that in respect of the images of the workmen in the colliery named in the chargesheet for the week ending 11-2-74 there has been double payment and it has also been mentioned in the chargesheet that out of these five workmen Sri Binod Bouri not having appeared in preliminary enquiry and Sri Panwa Bhuiya having received double payment the workman concerned has misappropriated the wages of Jaga Bouri, Gouri Bouri and Balaram Bouri for one week i.e. week ending on 11-4-74. The chargesheet says that the concerned workman has been charged with dishonesty in connection with company's business which is a misconduct. From this it appears that all the material allegations against the workmen have clearly stated in the chargesheet. The two wagesheets under which there have been double payment in respect of the aforesaid five workmen have been produced in the case. These documents show that there has been double payment as mentioned in the chargesheet. Further as has been pointed out earlier the specific charge against the concerned workman is, according to the management which held a preliminary enquiry, that the workman has misappropriated the wages of three workmen atleast for the week ending 11-2-74. The case, therefore, against the workman as mentioned in the chargesheet is very clear. No prejudice can be said to have been caused to the workman because particular provision of the Standing Orders has not been referred to in the chargesheet. The law on the point is well settled according to which when all material facts under which a workman is charged for misconduct have been clearly mentioned in the chargesheet the mere omission on the part of the management to refer to the relevant provision of the Standing Orders under which the workman is charged would not be fetal. Therefore, in my view no fault can be found with the management for non-mention of the relevant provision of the Standing Orders in the chargesheet under which the workman concerned has been chargesheeted with dishonesty. The word 'dishonestly' has not been defined either in the Model Standing Orders or in the Standing Orders referred to by Mr. Bose. Therefore, we have to fall back on the definition of the word 'dishonestly' as given in Indian Penal Code. According to the definition whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing 'dishonestly'. Intention has to be gathered from circumstances and no tangible evidence can be led to prove intention. The workman concerned admits that he was entrusted with the work for making payment to the workmen of the colliery. He gets the money to be paid from the cashier. The two wagesheets which have been marked as Ext. M-7 in the case show that there have been double payment to the five persons named in the chargesheet for the same week ending on 11-2-74. They also show that on the same date i.e. 18-2-74 payments have been made by the concerned workman. This position is not disputed. It is not the case of the workman that he made payment twice because there was some difficulty in identifying the five persons. The wagesheets also bear the thumb mark of the workmen who have been paid. Mr. Bose however contends that unless the thumb marks are proved to be not genuine by the management by examination of an expert the workman cannot be found to be guilty. I am unable to accept this contention. The fact remains as evident by the two wagesheets that there have been double payment to five persons for the week ending 11-2-74. Who has received the wages in which of the two wagesheets is of no importance. The workman concerned has made payments under both the wagesheets on the same date. This act itself unless it is shown by the workman concerned that he had no guilty intention behind must be held to be an act of dishonesty on his part. Whether there has been misappropriation or not is a different matter. There can be no doubt that the workman concerned is guilty of dishonesty in respect of company's business or property because by his act he caused wrongful loss to the company. According to me even if there has been no misappropriation as claimed by Mr. Bose and even if it is said that a case of misappropriation has not been established against the concerned workman still there can be no escape from the conclusion that the workman is guilty of misconduct for acting dishonestly. The charge therefore against the workman has been proved on his own admission that he made payments twice under the two wagesheets to the same set of workers for the same week on the same day. The misconduct proved against the workman entails the punishment of dismissal. The acts complained of against the workman are of very serious nature and for the maintenance of strict discipline and in the interest of administration the managemet's action in inflicting punishment of dismissal against the concerned workman cannot be said to be unjustified. Case of untair labour practice or victimisation though pleaded by the workman no evidence has been led in support of the plea. The punishment is fully justified in view of gravity of the offence. Lesser punishment in a case of this nature is not warranted.

5. I now take up the case of Sri P. C. P. Lala the concerned Bill Clerk. The chargesheet against the workman is that he billed Wages of S/Shri Jaga Bouri and Binod Bouri as trammer although they were stackers for the week ending 11-2-74. For the same week the bill for the same two workers has also been prepared by Sri Ram Lakan Shaw as stackers. The chargesheet further says that so far as Jaga Bouri is concerned it has been revealed in preliminary enquiry that he has received payment once only. On these allegations Sri P. C. P. Lala has been chargesheeted with dishonesty in connection with company's business. It is not disputed that wagesheets are prepared on the basis of the attendance register of the workmen. The Attendance Register filed in the case shows that Jaga Bouri and Binod Bouri worked for the week ending 11th February, 1974 as stackers and not as trammers. Both wagesheets on which payments have been made on 18th February, 1974 bear the signatures of workman Sri P. C P. Lala. The workman, however, says in his evidence that one of the two bills was prepared by Ram Lakhan Shaw. He of course admits that Ram Lakan Shaw is only a helper and helps him (Sri P. C. P. Lala) in preparing bills. The two wagesheets in the case have been signed by Sri Lala and his signatures appear under the column "made by". This being the state of record there can be no escape from the conclusion that the concerned workman prepared the two wagesheets may be with the help of Ram Lakan Shaw. The responsibility for preparation of two wagesheets vested with the concerned workman and therefore the two wagesheets bear his signatures as their author. At this stage it may be said that the other workman Ram Lakan Shaw who helped Sri Lala in preparation of these wagesheets was also charged for dishonesty. Dishonesty having been proved in the domestic enquiry Ram Lakhan Shaw was dismissed from service by the management. The order of dismissal of Ram Lakan Shaw was the subject matter of another reference in which Sri Shaw was found not guilty and so was reinstated with full back wages. This, however, is not a mitigating circumstance so far as Sri Lala is concerned. There is no justification why for the same set of persons wagesheets would be prepared twice for the same week. The workman concerned states in his deposition that he prepares wagesheets not only on the basis of attendance register but also on the basis of slips issued by higher authorities as well as on the oral instruction of the manager. This may be true but no positive case has been made out by the concerned workman that he prepared the wagesheets on the basis of some slips issued by higher authorities or on the basis of some oral direction given by the manager concerned. No evidence has also been led on the point. It must, therefore, be held that the two wagesheets were prepared on the basis of attendance register. The entries in the Attendance Register do not indicate that bills for the same set up persons could be prepared twice for the same week. Further the entries in the Attendance Register show that Jaga Bouri and Binod Bouri worked for the week ending 11th February, 1974 as stackers. The concerned workman does not say how he billed the wages of these two workers under the wagesheet prepared by him as trammers. Whether as a result of this double billing the concerned workman misappropriated the wages for Joga Bouri and Binod Bouri under one of the two wagesheets is a different matter. The fact that bills for the same set of persons were prepared twice is itself an act of dishonesty provided the intention in preparing the bills is to either make wrongful gain or wrongful loss. Intention is a thing which has to be gathered from circum-

stances. No plausible explanation by the concerned workman as to under what circumstance he prepared the two bills for the same set of persons twice and that also contrary to the entries made in the Attendance Register is forthcoming. It is not disputed that a trammer gets higher wage than a stacker. In the absence of any reasonable explanation to show that the concerned workman had no guilty intention in preparing two wagesheets, it must be said that he did so with an intention to cause wrongful gain to one and to cause wrongful loss to the company. Dishonesty in respect of company's business and property is a misconduct under the Standing Orders which governs the colliery in question. That being so it cannot but be said that the concerned workman has been rightly found to be guilty in the domestic enquiry. The punishment of dismissal inflicted upon the concerned workman for misconduct cannot be said to be not justified. A dishonest act like the present one cannot be encouraged in any way in the interest of good administration. The punishment inflicted on the workman therefore deserves no interference as the same cannot be said to be disproportionate to the charge.

6. The reference is answered accordingly. There will be no order for costs.

Sd/-

B. K. RAY, Presiding Officer.

[No. L-20012/42/72-D.III(A)] and
L-20012/36/75-D.III(A)]

New Delhi, the 20th August, 1980

S O 2269.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act. 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal No. 2, Dhanbad, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited. Post Office Sonardih, District Dhanbad and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th August, 1980.

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (NO. 2) DHANBAD

PRESENT :

Shri J. P. Singh, Presiding Officer.

Reference No. 81 of 1979

In the matter of a reference under S. 10(1)(d) of the

I.D. Act, 1947

PARTIES :

Employers in relation to the management of Area No III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad.

AND

Their workmen

APPEARANCES :

On behalf of the employers—Shri B. Joshi, Advocate.

On behalf of the workmen—Shri B. Lal, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal.

Dhanbad, 6th August, 1980

AWARD

This is a reference under S. 10(1)(d) of the I.D Act. 1947. The Central Government by its notification No. L-20012/86/77-D.III(A) dated 19th October, 1977 had referred this dispute to the Central Government Industrial Tribunal (No.3) Dhanbad for adjudication on the following terms :

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post Office Sonardih, District Dhanbad in stopping Shri D. P. Singh, office Peon from work with effect from the 15th November, 1976, is justified ? If not, to what relief is the said workman entitled ?"

2. This dispute was raised by Koyala Ispat Mazdoor Panchayet. The concerned workman Shri Deo Pujan Singh was a member of that union. He was appointed on 3-12-72 at Pure Jairamdih colliery which was later amalgamated with other collieries and formed into an unit known as Benedih colliery. In June, 1975 Shri Deo Pujan Singh was transferred from Benedih colliery to the Regional Store situated at Kharkhari. This Regional Store was shifted from Kharkari to Sinidih in the last part of 1975. In November, 1976 he was transferred to Bhagatdih building of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. as office peon where he worked upto 13-11-76. He was stopped from work on 14-11-76 by order of General Manager, Area No. III vide his letter No. GM|AR.III|PD| 16993 dated 12|13-11-76. It was alleged that the workman had been identified as imposter by a team of officers of the headquarters and therefore he was stopped from work. The workman in his application dated 30-11-76 requested the Director (Personnel) M/s. Bharat Coking Coal Ltd. to allow him to resume duty on the basis of certificate with his attested photo granted by the Circle Officer, Garkha Block, Dist. Saran. A copy of the certificate was also submitted to the General Manager, Area No. III. The workman after waiting for a response to his application and not getting the same from any quarter, approached the union for help. The union through its letter dated 29-11-76 requested the Assistant Labour Commissioner(C) to take up the matter in conciliation and also to get the workman reinstated with retrospective effect. The Assistant Labour Commissioner(C) called several meetings of the parties on various dates from January, 1977 to March, 1977 and ultimately submitted his failure report on 28th March, 1977. The Government of India, Ministry of Labour through its letter dated 19-10-1977 refererd this dispute to the Central Government Industrial Tribunal (No. 3) Dhanbad for adjudication. Thereafter this reference was transferred to this Tribunal for disposal.

3. The employers in relation to the management of Area No. III of M/s. Bharat Coking Coal Ltd. filed their written statement. It was contended that the present reference was not legally maintainable on account of a valid settlement arrived at in the course of conciliation proceeding under Section 12 of the I.D. Act, 1947. It was submitted that during the subsistence of a settlement recorded under S.12(3) of the I.D. Act, 1947 no industrial dispute can be referred to any Industrial Tribunal for adjudication. On point of fact it has been stated that the colliery was taken over w.e.f. 31-1-1973. In 1976 it was detected that a large number of inductee/imposters were working in various units of Benedih colliery. The management stopped all such workmen from work and the trade unions operating in that colliery gave a strike notice, Conciliation machinery acted with due deligence to avoid strike and a conciliation settlement was arrived at between the management and the union. In the settlement the workmen who had been stopped from their duties as inductees/imposters were divided into 3 groups viz., A, B & C. A comprehensive settlement was arrived at so that the workmen named in group A & B were re-instated with the condition of service stipulated in the aforesaid settlement. The workmen listed in Group C were dropped. The concerned workman Sri Deopujan Singh was in the list of Group C. According to the management the concerned workman was found on the basis of documents to be an inductee/imposter and had been stopped from work. It was alleged that his name was entered in the statutory registers after manipulation & falsification of documents. This was done after the take over of the management with the connivance of certain interested persons who were seperately dealt with by the management. The management further contended that the name of the concerned workman did not appear in the initial Man Power list.

4. At the instance of the management a decision was sought on the question as to whether the reference was maintainable in view of the settlement which was in operation at the time when this reference was made. The parties have been heard.

5. While discussing the question of maintainability of this reference we have to keep in mind certain events. The concerned workman was stopped from work on 15-11-76 and the Koyala Ispat Mazdoor Panchayat had raised this dispute in December, 1976. By March, 1977 a failure report was submitted to the Government of India, Ministry of Labour on the basis of which this reference was made in

October, 1977 for adjudication. But in the meantime two other unions viz. Koyala Mazdoor Union and Rastriya Colliery Mazdoor Sangh had served a strike notice with charter of demands. One of the demands was that the workmen (alleged imposters) who were made forced idle in 1975 and 1976 should be reinstated with back wages. The first strike notice is dated 6-7-77 and the second one dated 7-7-77. The settlement arrived at was on 19-7-77. In the settlement the case of imposters/inductees of Benedih Colliery had been taken up between the management and the two aforesaid unions—Koyala Mazdoor Union and Rashtriya Colliery Mazdoor Sangh. Koyala Ispat Mazdoor Panchayat was not a party to this dispute or to the settlement. It has been pointed out on behalf of the workmen that since the concerned workman or the union was not party to the dispute which ended in settlement, such a settlement was not binding on the workman or the union. It was further pointed out that the Assistant Labour Commissioner had negotiated with the management for the settlement of the dispue between the management and the concerned workman and his union but the same ended in failure and a failure report was submitted to the Government of India, Ministry of Labour before any dispute on the same point was taken up by the two other unions viz. Koyala Mazdoor Union and Rastriya Colliery Mazdoor Sangh which resulted in conciliation settlement. On this score it is said that the reference made on the failure report in the case of the concerned workman could not be barred by any subsequent settlement. Another point which has been taken is that in the settlement the cases of 28 persons including the concerned workman as mentioned in Group C were dropped. The word "dropped" has been interpreted on behalf of the workman to mean that their cases were not considered by the management and the two unions which would go to show that with regard to persons mentioned in Group C no conciliation settlement was arrived at. On the strength of this interpretation it has been argued that the reference is maintainable.

6. The first two points raised on behalf of the workman is answered by the provisions of clause (d) of Sub-section (3) of S. 18 of the I.D. Act, 1947. It is an admitted position that this workman along with several others were stopped from work by the management of the same establishment. In order to bind the workman it is not necessary to show that the said workman belong to the union which was party to this dispute before the conciliator. The whole policy of S.18 appears to be to give an extended operation to the settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or adjudication proceedings. In Tiruchi Srirangam Transport Co. Ltd. v. Industrial Tribunal (1962—I.L.L.J.—Page 94) the single Judge Veeraswami J. held a different view which could be usefully applied in this case on behalf of the workman. But later decisions of the Madras and other High Courts held that the view of Veeraswami J. did not appear to be correct. The different High Courts have followed the Supreme Court decision in Ramnagar Cane and Sugar Company Ltd. v. Jatin Chakravorty (1961—I.L.L.J. 244) in which Gajendragadkar J. held the following :

> "In other words, there can be no doubt that the settlement arrived at between the appellant and the employees' Union during the course of conciliation proceedings on February 25, 1954, would bind not only the members of the said Union but all workmen employed in the establishment of the appellant at that date. That inevitably means that the respondents would be bond by the said settlement even though they may belong to the rival Union. In order to bind the workmen it is not necessary to show that the said workmen belong to the union which was a party to the dispute before the conciliator. The whole policy of S. 18 appears to be to give an extended operation to the settlement arrived at in the course of conciliation proceedings, and that is the object with which the four categories of persons bound by such settlement are specified in S. 18 sub-section (3)".

7. It will thus appear that the plea of the workmen that he and his union had seperately raised the dispute which before the dispute was raised by two other unions on the same point ended in conciliation settlement, could not make this reference maintainable. Since the concerned workman belongs to same establishment along with other workmen and there was a conciliation settlement, such a settlement was binding on him also.

595 GI/80—7

8. Now let us take up the third and the last point taken up by the workman, I have already said the concerned workman appears in Group C. Sl. No. 28 of the settlement, Ex. M1. It has been said therein that the case of Group C workmen were dropped by the union representatives as per settlement. Paragraph 5 of the settlement deals with the concerned workman and others of Group C reads :

> "The Union agreed to drop the cases of the workmen whose names are mentioned in Annexure C and they will not raise this point in future."

We know now that according to the concerned workman the interpretation of the word "dropped" is that the cases of persons mentioned in Group C were not considered under this settlement so as to have any binding effect on them. The learned Advocate appearing on behalf of the concerned workman has referred to L.L.J.—Vol. II 1965 Page 149. In this case certain items of dispute were not pressed and withdrawn by the workmen under the terms of settlement, and therefore no award was given in respect of such items. It was held that in respect of such items of dispute which were withdrawn and did not form subject matter of settlement or award could not be a bar to the workmen raising such demands and getting the same for adjudication under S.10 of the I.D. Act. In this settlement, Ext. M1 the unions had raised more than one demands and on all the demands there had been settlement. What I mean to say is that none of the demands were dropped. The management has contended that Group A & B workmen were re-instated and Group C workmen were not re-instated. By the word "dropped" as mentioned in settlement with regard to Group C workers it was intended to be conveyed that they were given no relief under the settlement. At any rate the law relied upon by the concerned workman, as pointed out earlier, is not applicable to the present case. It is clear that the settlement Ext. M1 also binds the concerned workman.

9. Thus having considered all aspects of the case it is held that the concerned workman is bound by the settlement Ext. M1 under which the case of his continuing in the services of Bharat Coking Coal Ltd. was concluded under the settlement. The same matter cannot be reagitated in this Reference because the subject matter once concluded by a conciliation settlement could not be re-agitated in a subsequent reference. This reference, therefore, has to be disposed of on preliminary point.

10. I accordingly hold that the action of the management of Area No. III of Messrs Bharat Coking Coal Limited, Post office Sonardih, District Dhanbad in stopping Shri D. P. Singh, office peon from work with effect from the 15th November, 1976 is justified. Consequently, the workman is entitled to no relief.

This is my award.

J. P. SINGH, Presiding Officer.

[No. L-20012/42/75-D.III(A) and L-20012/36/75-D.III(A)]

S. H. S. IYER, Desk Officer

New Delhi, the 22nd August, 1980

S.O. 2270.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the following award of the Central Government Industrial Tribunal, Jabalpur, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Bank of Maharashtra, Pune and their workmen, which was received by the Central Government on the 14th August, 1980.

BEFORE SHRI A. G. QURESHI, M.A., LL.B., PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, 724 NAPIER TOWN, JABALPUR (M.P.)

Case No. CGIT/LC(R)(37)/1979

PARTIES :

Employers in relation to the Management of Bank of Maharashtra, Pune and their workmen represented through the Union of the Maharashtra Bank Employees, Arun, Bhavan, Temple Bazar Road, Sitabuldi Nagpur-12(M.S.)

APPEARANCES :

For Union—Shri Satish Trimbak Saharabudhe and Shri Kishor Narayan Undar

For Bank—Shri A. S. Pote, Law Officer

INDUSTRY : Bank DISTRICT : Nagpur (M.S.)

AWARD

Dated : July 30, 1980

The Government of India in the Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred to it by Clause 10(1)(d) of the Industrial Disputes Act, 1947, has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication by its Order No. L-12012/69/79-D-IIA dated 12-12-1979 :—

"Whether the management of Bank of Maharashtra Pune was justified in denying promotion to Shri S. B. Dhakata, Clerk, Chandrapur branch to the post of Junior Officer with effect from 16th June, 1978 ? If not to what relief the concerned workman is entitled ?"

2. It is not in dispute that the management of the Bank of Maharashtra vide settlement dated 29-6-1976 with the Union of the Bank employees of Maharashtra formulated a promotion policy for internal promotion from clerical cadre to the post of junior officers. According to the promotion policy 15 per cent posts were reserved for Scheduled Caste and 7-1/2 per cent were reserved for the Scheduled Tribes members of the staff in the clerical cadre of the Bank, for promotion to the post of junior officers. It is also not in dispute that vide notification No. AX1|ST|SPL.|4|78 dated 13-1-1978 the applications from the staff members were invited for promotion to the post of junior officers. The promotion was to be made on the basis of selection from amongst the clerks who fulfilled the conditions laid down in the notification. The result of the examinations conducted by the management for promotion was declared on 24-5-1978, by which 150 vacancies of officers were filled, out of which first 146 candidates were selected from the general candidates and 4 from amongst the SC/ST candidates. The list of the general candidates was decared under head 'A' and that of SC/ST under head 'B'.

3. It is also uncontroverted that Shri S. B. Dhakata an S. T. employee of Chandrapur was placed at no. 6 in order of merit in the list of SC/ST candidates, Shri Dhakata could not be promoted to the post of Junior Officer, he being placed at no. 6. It is also an admitted position that Shri Dhakata made a representation before the Divisional Manager, Bank of Maharashtra, Pune vide Ex. W/17 stating therein that according to the reservation quota, the total number of the seats for the SC/ST candidates should have been 33. As only 10 candidates of SC/ST candidates had passed in the written test, all of them should have been selected in terms of the circular issued reserving the seats for SC/ST candidates. The General Secretary of the Bank Employees Union also made a representation to the management (Ex. W/18) submitting therein that Shri Dhakata should have been promoted to the post of Junior Officer according to the policy formulated for promotion.

4. The case of the Union is that the management by its settlement dated 29-6-1976 with the Union agreed to fill up certain vacancies by promotion from the clerical cadre of the Bank and accordingly formulated a policy for promotion, according to which amongst other conditions, 15 per cent and 7-1/2 per cent posts were to be reserved for SC/ST candidates respectively. The Bank besides examinations in the year 1976, 1977 conducted a promotional test and interview vide Bank Circular dated 13-1-1978 for filling in 150 posts of junior officers subject to reservation of 15 per cent and 7-1/2 per cent for SC/ST candidates. Shri S. B. Dhakata, a clerk at Chandrapur branch and a Scheduled Tribe candidate, qualified himself in the above test and thus became eligible for promotion with effect from 16-6-1978. The management, however, did not promote Shri Dhakata inspite of representations made by the candidate and the Union.

According to the Union, the Bank has not adopted uniform policy for selection of candidates and the Bank has violated the policy formulated by it, and the Government directions, in not promoting Shri Dhakata from 16th June, 1978. Therefore, Shri Dhakata be declared promoted to the post of Junior Officer with retrospective effect i.e. from 16-6-1978.

5. The management has resisted the claim on the ground that Shri Dhakata was sixth in the merit list prepared for SC/ST candidates, whereas the management found only 4 candidates, from amongst the SC/ST, fit for promotion. Therefore, Shri Dhakata could not be promoted. Shri Dhakata, of course, passed in the written test and was interviewed but it does not give him any right of promotion in an objective type of promotional test. The management has not violated its promotion policy and Government directives.

According to the management, in all 300 vacancies of the officers were to be filled by the management by way of promotion from clerical staff for the year 1978. For the sake of convenience a promotion programme consisting of two examinations, one on 19th February, 1978 and the second on 17th December, 1978, were planned. As per the Government guidelines 68 seats were reserved for SC|ST candidates vis-a-vis the total 300 vacancies. Shri Dhakata had appeared for the test of 19-2-1978. In this examination, in all 10 SC/ST candidates could qualify for interview after the necessary relaxation given to them. However, out of them only 4 candidates were finally found fit for promotion by the interview Board and accordingly they were selected.

6. From the above pleadings, the question that arises for determination is whether the management was justified in denying promotion to Shri Dhakata by not selecting him in the first examination held in February 1978.

The only justification for not selecting Shri Dhakata, advanced by the management, is that Shri Dhakata could not secure the minimum marks for selection, which according to the management, were cut off marks. The stand of the management is that in the first list the last candidate selected from the general list had secured 133 marks out of 250 marks. As such the cut off marks were 133, whereas Shri Dhakata got only 122.10 marks even after relaxation of 5 per cent marks to him. Therefore, Shri Dhakata could not be selected.

7. In my view, this stand of the management cannot be held to be justified for the simple reason that from the documents filed by the management itself, it is manifest that the management has not followed a uniform policy in selecting the candidates for promotion to the post of junior officers.

It is a common ground that according to the policy (Ex. W/14) formulated by the management 15 per cent and 7-1/2 per cent seats were reserved for SC & ST employees respectively. The management wanted to fill in 300 vacancies by way of promotion from clerical staff to the post of junior officers. As such, 68 seats were reserved for SC & ST candidates out of the 300 vacancies. Initially the management invited applications only for 150 vacancies out of which 34 vacancies were reserved for SC & ST candidates, but only 10 persons from SC/ST candidates could qualify for interview. But the management after an interview selected only 4 persons and instead of carrying forward the vacancies reserved for SC/ST filed the remaining vacancies by appointing candidates from the general list. It is pertinent to note that although the vacancy was available still Shri Dhakata was not promoted because according to the management, he secured lesser than the out off marks. As such, according to the pleadings of the management, the policy of the management was to select

only those persons who secured at least the cut off marks i.e. the last qualifying marks obtained by the candidate in the general list. But the result of the test held on 17-12-78 tells a different tale.

8. The result of the examination held on 17-12-1978 was declared on 5th March 1979 which is Ex. M/1, according to which out of 150 vacancies only 100 were filled and 50 remaining vacancies were carried forward for the SC/ST employees. Out of 100 vacancies 86 were filled by general list and 14 by SC/ST candidates. Annexure to Ex. M/1, which is the result of the test, shows that in Category 'A' the cut off marks were 138 i.e. the marks obtained by the selected candidate no. 86 in the general list, whereas in 'B' list prepared out of the SC/ST candidates, only 1 candidate, Shri Kamle could get more than the cut off marks i.e. 142.15 marks and all the remaining 13 candidates could not get marks equivalent to cut off marks, still all the 14 candidates (including Shri Dhakata, who secured less than the cut off marks) from SC/ST were declared selected. Candidate no. 14 Shri Langian, in the SC/ST list got only 105.68 marks, which are much less than the cut off marks.

9. The aforesaid result clearly shows that the policy of the Bank while declaring result of the second examination was to prepare two different lists, one for general candidates and the other for SC/ST candidates; and even if SC/ST candidates did not get the cut off marks, they were selected if they were otherwise found fit for selection to the higher post. The policy of the Government regarding relaxation of standard for SC/ST candidates has been, that if the total vacancies reserved for SC/ST cannot be filled on the basis of general standard; candidates belonging to these community will be taken by relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota subject to the fitness of these candidates for appointment to the post in question. It appears that the Bank Authorities were guided by the above principles, while declaring the result of examination held on 17-12-1978. As a result all the SC/ST candidates who were found eligible for interview i.e. who qualified in the written test for interview were declared selected.

10. There can be no two opinion that the management is excepted to follow a uniform policy in respect of recruitment of the candidates belonging to the same category and cadre. The policy followed by the management at the time of selecting the SC/ST candidates from amongst those who appeared on 17-12-1978 for examination was quite different from the one followed while selecting the candidates as a result of the examination held in February, 1978. If the management was of the view that because of the non-availability of candidates according to general standard to fill in the vacancies reserved for SC and ST candidates, the standard should be relaxed to such an extent that all the SC/ST candidates who qualified for interview should be selected (as has been done in case of second selection held on 17-12-78) then the management could not have denied promotion to Shri Dhakata on the ground that although he was qualified for interview but was not fit for promotion because he secured marks lessen than the cut off marks.

It will not be out of place to mention that when Shri Dhakata was rejected in the first interview he had obtained an aggregate of 122.10 marks when the cut off marks were 133. But in the next interview held in December 1978 although the cut off marks were 136 still Shri Dhakata was selected inspite of getting marks less than the cut off marks and the other SC/ST candidates getting 105.68, 108.68, 112.15, 113.25, 120.3 and 120.90 were declared selected.

11. It is not in dispute before me that the tests held in February and December 1978 were taken by the management under the common policy formulated for selection to the posts of junior officers from amongst the staff. The policy for reservation of seats for SC/ST candidates was also the same. Therefore, the management could not apply two different yard sticks for selecting the SC & ST candidates appearing for examination held on two different dates. The policy which has finally been followed by the management is to prepare a separate list of the SC & ST candidates, and subject to the availability of the reserved vacancies, to select those SC/ST candidates for the higher post, who although did not get the cut off marks according to the standard of general candidates, but were otherwise found fit for selection. It therefore follows that Shri Dhakata was eligible for selection in the first examination of February 1978 according to the aforesaid policy of selection and he was wrongly denied the promotion on the ground that he could not secure the cut off marks. Denying the promotion to Shri S.B. Dhakata in the first list is clearly an act of hostile discrimination between the candidates appearing at February and December 1978 tests.

12. From the aforesaid discussion, it is clear that the action of the management being arbitrary, capricious and discriminatory, amounts to unfair labour practice. I am aware of the settled position of law that promotion is purely a management's function and the Tribunal should not interfere in the action of the management unless it is not motivated by victimisation, malafides or unfair labour practice. In the instant case, as held above, the action of the management is clearly one of unfair labour practice and therefore I deem it proper to interfere with the decision taken by the manavement.

13. In the result, it is held that the action of the management in denying promotion to Shri S.B. Dhakata to the post of Junior Officer with effect from 16th June 1978 is not justified. According to the practice followed by the management in selecting Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates from amongst those who appeared at the tests held on 17-12-1978, Shri Dhakata should have been declared selected at Serial No. 146 in the result declared on 14th May, 1978. The total seats to be filled by the test held in February were 150. Out of which 34 were reserved for SC & ST candidates. However only 4 reserved seats could be filled by the general standard, so after relaxing the standard all the remaining 6 SC & ST candidates who had qualified for interview should also have been selected to fill up at least ten vacancies in the reserved quota and the remaining could be carried forward. Shri Dhakata was placed at No. 6 in the order of merit in the list prepared from the SC/ST candidates. So, if the management decided not to carry forward the unfilled remaining vacancies then it could have filled 140 vacancies from amongst the general candidates and 10 by the SC/ST candidates who had qualified for interview and who deserved to be selected for promotion according to the policy adopted by the management in the December test.

As such in the result declared on 24th May, 1978, Shri Dhakata should have been declared selected at No. 146.

14. Consequently, it is held that Shri Dhakata is entitled to get his seniority from 16th June, 1978 as junior Officer. He shall for the purposes of seniority be deemed to have been selected at No. 146 in the list of the selected candidates declared on 24-5-1978. However, Shri Dhakata, shall not be entitled to back wages and other benefits of the higher post, because he actually did not shoulder the higher responsibility of a Junior Officer till the date of his actual promotion to that post as a result of his selection in the second test held on 17-12-1978.

In the circumstances of the case, the management will pay Rs. 200 as costs to the Union.

An award is given accordingly.

A.G. QURESHI, Presiding Officer.

[No. L-12012/69/79-D. II. A]

S. K. BISWAS, Desk Officer.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980